राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण गुरुवार,१३ मई २०२१ वर्ष-४, अंक -१०९ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

यूपी-पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बारिश-आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश की ये आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और एक-दो स्थानों पर ओले गिरने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख के पूर्व में चला गया है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ईरान के पूर्वी हिस्सों और उससे सटे अफगानिस्तान पर देखा जा सकता है। वहीं, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिण अरब सागर के मध्य भागों में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इस कारण देश के अधिकांश राज्यों में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी भारत समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस सप्ताह भी राहत भरा रहेगा मौसम। तापमान सामान्य से नीचे रहेगा जबकि धूल भरी आंधी के भी आसार बने रहेंगे। अक्सर इन दिनों में गर्म हवा के थपेड़े परेशान करने लगते थे, लेकिन अभी तक इस वर्ष लू से राहत है। अगले सप्ताह से गर्मी अपना रंग दिखा सकती है।

अस्पताल में लगी भीषण आग, ICU में एडमिट थे 70 मरीज

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के एक अस्पताल में आग लगने की खबर फिर से सामने आई है। इस बार गुजरात के भावनगर में स्थित जनरेशन अस्पताल हादसे का शिकार हुआ है। यहां अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उस वक्त ढ्ढष्ट में एडमिट सभी मरीजों को बाहर निकले जाना लगा। बता दें कि ICU में 70 मरीज थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

अस्पताल प्रबंधन का कहना है ये

इस हादसे को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आग की सूचना मिलते ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह के बारे में प्रबंधन ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी लेकिन बिना किसी जान हानि के हमने आग पर काबू पा लिया।

इससे पहले इन अस्पतालों में भी लग चुकी है आग- आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंचा है उस वक्त से अस्पतालों में आग लगने की खबरे ज्यादा आ रही है। इससे पहले भी गुजरातके भरूच शहर के एक अस्पताल में आग लग गई थी। ये आग 30 अप्रैल की रात को लगी और आग की लपटे इतनी बड़ी थी उस आग में 14 मरीज समेत 2 स्टाफ नर्स की मौत हो गई थी। वहीं भरूच से पहले महाराष्ट्र का प्राइम क्रिटिकेअर अस्पताल भी आग के हादसे का शिकार बना था। इस अस्पताल में भी आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई थी।

- इस हादसे को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आग की सूचना मिलते ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह के बारे में प्रबंधन ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी लेकिन बिना किसी जान हानि के हमने आग पर काबू पा लिया।
- इससे पहले इन अस्पतालों में भी लग चुकी है आग- आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंचा है उस वक्त से अस्पतालों में आग लगने की खबरे ज्यादा आ रही है। इससे पहले भी गुजरातके भरूच शहर के एक अस्पताल में आग लग गई थी।

छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों की कोरोना से मौत,15 से 20 की हालत गंभीर

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक नेता से मिले पत्र से पता लगा है कि यहां लगभग सात से आठ माओवादी कैडर कोविड -19 से मर चुके हैं और लगभग 15 से 20 अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं। बस्तर महानिरीक्षक सुंदरराज ने बताया कि आज बीजापुर में एक ऑपरेशन के दौरान, सीपीआई (माओवादी) के एक कैडर द्वारा एक वरिष्ठ नेता को लिखे गए एक पत्र को जब्त कर लिया गया था। पत्र में बताया गया है कि 7-8 कैडर कोविड-19 से मर चुके हैं और लगभग 15-20 अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास जानकारी है कि कुछ नक्सलियों ने कोरोना डर से कैडर छोड़ भी दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में 9,717 नए मामले और 199 मौतें सामने आई। साथ ही 12,440 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए है।

आरोपी की सहूलियत के आधार पर क्रिमिनल केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी की सहूलियत के आधार पर आपराधिक मुकदमों को एक राज्य से दूसरे राज्य के कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुकदमे यदि दूरी तय करने के आधार पर स्थानांतरित करते रहे तो सीआरपीसी में तय किए गए मुकदमे चलाने के कोर्ट के क्षेत्राधिकार के प्रावधान बेमतलब हो जाएंगे। जहां तक कानून के निर्देशों का सवाल है तो वहां सुविधा और असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एकल पीठ ने यह फैसला एक मुकदमे को तमिलनाडु के सेलम से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्थानांतरित करने की सीआरपीसी की धारा 406 के तहत दायर अभियुक्त की स्थानांतरण याचिका को खारिज करते हुए दिया। धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक ही राज्य से दूसरे राज्य में मुकदमे स्थानांतरित करने का मूल अधिकार है। जबकि राज्य के अंदर ही मुकदमे एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में भेजने का अधिकार संबंधित हाईकोर्ट को होता है।

भाषा की दिक्कत के आधार पर केस स्थानांतरित नहीं किया जा सकता-कोर्ट ने कहा कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो या तो अभियुक्त को या शिकायतकर्ता को पूरे राज्य में यात्रा करके केस की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय अधिकार वाले कोर्ट में जाना पड़ता है। यहां तक कि भाषा की दिक्कत के आधार पर केस स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इस मामले में अभियुक्त ने कहा था कि उसे तमिल समझ नहीं आती इसलिए उसका मामला दिल्ली भेजा जाए। धारा 406 के तहत मुकदमा तभी स्थानांतरित किया जाता है जब न्याय सुनिश्चित करना हो और यह न्याय उस राज्य में सुनिश्चित करना संभव नहीं हो रहा हो।

आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में संबंधी हैं-कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में संबंधी हैं और उन्होंने पेटेंट संबंधी दीवानी मुकदमे अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली और तमिलनाडु में दायर किए हैं। लेकिन अब आरोपी एक आपराधिक मुकदमे को 2000 किमी की दूरी के आधार पर स्थानांतरण मांग रहा है।

रेलवे के हजारों आइसोलेशन कोच तैयार, लेकिन नहीं आ रहे मरीज

नई दिल्ली। कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद रेलवे द्वारा आइसोलेशन के लिए उपलब्ध कराए गए 4000 से ज्यादा कोच का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह कोच देश के विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध हैं, लेकिन राज्य सरकारें इनका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। इन कोचों में अभी तक 200 मरीज भी नहीं पहुंचे हैं। रेलवे में पिछली बार की तुलना में इन कोचों को ज्यादा सुविधाजनक बनाया है।

रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने बताया है कि रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 4176 कोच को आइसोलेशन कोच के रूप में तब्दील कर पूरी तरह तैयार कर रखा है। इनमें से कई कोच को देश के विभिन्न राज्यों के स्टेशनों पर तैनात भी किया गया है। हालांकि इनमें मरीज बहुत कम आ रहे हैं। कई स्टेशनों पर तो अभी तक एक भी मरीज नहीं आया है। इसकी एक वजह इन कोच में सिर्फ कोरोना संक्रमित और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए ही सुविधाएं हैं। आईसीयू न होने के कारण गंभीर स्थिति वाले मरीजों को यहां पर नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा इन कोच का प्रबंधन राज्य सरकारों को अपने हाथ में लेना होता है और जब तक वह इनको किसी अस्पताल से जोड़े नहीं तब तक वे मरीजों को इनमें रखने का जोखिम नहीं ले पाती हैं। डॉक्टरों और मेडीकल स्टाफ की कमी राज्यों के आड़े आती है।

स्टेशन-आइसोलेशन कोच- कितने मरीज

दिल्ली में शकूरबस्ती- 50 (800 बेड)- 5
आनंद विहार- 25 (400 बेड)- 00
महाराष्ट्र में नंदुरबार- 24 (378 बेड)- 120
पालघर- 24 (336 बेड)- 3
भोपाल- 20 (292 बेड)- 30

2-18 आयुवर्ग के लिए भारत में होगा कोवैक्सीन का दूसरा/ तीसरा फेज का ट्रायल

नई दिल्ली। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2-18 आयुवर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के लिए क्लीनिकल टेस्ट की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा।

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को भारत बायोटेक द्वारा किए गए उस आवेदन पर विचार-विमर्श किया जिसमें उसके कोवैक्सीन टीके की दो साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे/तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

एक सूत्र ने कहा कि कंपनी के आवेदन पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्तावित दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दिए जाने की सिफारिश की।

टीकाकरण: राज्यों के द्वारा खरीद के लिए वैक्सीन की सिर्फ 2 करोड़ खुराक, केंद्र ने तय किया कोटा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया गया है। इसके मुताबिक, राज्य सरकारों को 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में करीब 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18-44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या के आधार पर इन दो करोड़ खुराक को राज्यों को भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुराक को समान रूप से वितरित किया जाए। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उनका आवंटन अपर्याप्त है। बीते सप्ताह के अंत में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है, राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 (वर्ष) की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित की है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की खरीद करेंगे, ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो। भारत में फिलहाल दो आधार पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। एक 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को खुराक दी जा रही है। वहीं, 18-44 वायु वर्ग के लोगों को भी एक मई से टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए निः शुल्क खुराक दे रही है। केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन निर्माताओं के लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक, व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे दोनों शॉट्स भारत में बनाए गए हैं। कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करना है। इसके बाद की वैक्सीन को कंपनी निजी खरीददारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है। राज्य सरकारों द्वारा सीधे अधिग्रहण के लिए इस महीने आवंटित की गई दो करोड़ खुराक केवल 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में दीजाने वाली हैं। बाकी, दो मिलियन से अधिक की शॉट्स का उन्हें भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं।

क्या देश को फिर लॉकडाउन की जरूरत ?

चीन में कोरोना काफी कम मगर प्रतिबंध भारत से कहीं कड़े

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वाले चीन में अब संक्रमण की गति बिल्कुल मंद पड़ चुकी है फिर भी यहां बेहद कड़े प्रतिबंध लागू हैं। दूसरी ओर, भारत इस वक्त दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है पर यहां लागू प्रतिबंध चीन के मुकाबले कम कड़े हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंगरेंसी इंडेक्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है। यह सूचकांक अलग-अलग देशों में संक्रमण से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल, भारत में कोरोना की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां अब हर दिन करीब औसतन चार लाख मामले सामने आ रहे हैं।

चीन ने लगातार जारी रखी कड़ी पाबंदी

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंगरेंसी इंडेक्स के हिसाब से चीन में इस वक्त सौ प्रतिशत में से 78.24 प्रतिशत सख्तियां लागू हैं। चीन में लगाई गई पाबंदियों का ग्राफ देखने पर पता लगता है कि यहां जनवरी 2020 से लेकर आजतक औसतन 75 प्रतिशत सूचकांक के प्रतिबंध लागू हैं। जबकि चीन में संक्रमण की स्थिति में मार्च-2020 के बाद से ही सुधार आने लगा था। अब चीन में हर दिन

औसतन पांच नए मरीज ही मिल रहे हैं। हालांकि बीच-बीच में चीन के कुछ क्षेत्रों में संक्रमण का विस्फोट होता रहा है, जिस पर चीन ने बिना समय गंवाए कड़े प्रतिबंध लगाकर काबू पा लिया। इतना ही नहीं, चीन ने 81 प्रतिशत सूचकांक वाले बेहद कड़े प्रतिबंध पिछले साल चार बार फरवरी, मई, सितंबर और नवंबर में लगाए थे।

भारत में पाबंदियां 74 फीसदी कठोर

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंगरेंसी इंडेक्स के मुताबिक, वर्तमान में भारत में लागू प्रतिबंधों की कठोरता 73.61 प्रतिशत है। प्रतिबंधों की कठोरता का यह स्तर 19 अप्रैल से बना हुआ है। इससे पहले 10 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक देश में संक्रमण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में जबरदस्त ढील दी गई थी, तब प्रतिबंधों की कठोरता का स्तर 57.87 प्रतिशत था जो कि पिछले साल 25 मार्च को लागू हुई तालाबंदी के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। यह दर्शाता है कि 15 फरवरी से संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद देश में मार्च के महीने में आवश्यक पाबंदियां नहीं लगायी गई।

पिछले साल लगा था शत-प्रतिशत कड़ा लॉकडाउन

ऑक्सफोर्ड के सूचकांक के मुताबिक, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जहां राष्ट्रीय लॉकडाउन की कठोरता 100 प्रतिशत थी। भारत में 25 मार्च से 19 अप्रैल तक यह सर्वाधिक कठोर तालाबंदी लागू रही। इसके बाद 22 अप्रैल से 29 सितंबर तक 96 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की कठोरता वाली पाबंदियां लागू रहीं। इसके बाद पाबंदियों में लगातार ढील देना जारी रहा, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं।

इस तरह नापते हैं प्रतिबंधों की कठोरता

ऑक्सफोर्ड नौ इंडीकेटर के आधार पर यह पता लगाता है कि किसी देश में लागू प्रतिबंधों में किस स्तर की कठोरता है। इसमें स्कूलबंदी, कार्यस्थल बंदी, यात्रा प्रतिबंध, सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी, घर तक सीमित रहना, सार्वजनिक यातायात समेत नौ मानकों को शामिल किया गया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

वैक्सीन की कमी

कोरोना की मौजूदा लहर में जो अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं, उनमें से एक है टीके की कमी। अगर इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत युद्ध स्तर पर उपाय नहीं किए गए, तो यह समस्या आने वाले वक्त में और गंभीर होती जाएगी। भले ही यह लहर खत्म हो जाए, लेकिन कोरोना पर स्थाई नियंत्रण के लिए जरूरी है कि देश की कम से कम 50-60 प्रतिशत जनसंख्या को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। केजरीवाल ने यह सुझाव भी दिया है कि केंद्र सरकार वैक्सीन का फॉर्मूला दो कंपनियों से लेकर ज्यादा कंपनियों को दे, ताकि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ सके। इन दो कंपनियों को अन्य कंपनियां इसके लिए कुछ रॉयल्टी दे सकती हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि ये दोनों कंपनियां अभी तकरीबन छह-सात करोड़ खुराक ही हर महीने बना पा रही हैं और इस तरह पूरे देश के टीकाकरण में बरसों लग जाएंगे। केजरीवाल की फिक्र जायज है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी मुख्यमंत्री इस विषय पर कुछ बोलें। इसकी वजह यह है कि वैक्सीन की कमी का सबसे बड़ा खामियाजा राज्य सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक, राज्य सरकारों को कुल उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत ही मिलेगा, जबकि 18 से 44 की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। फिर अलग-अलग राज्यों से मांग के मुताबिक वैक्सीन न दिए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। एक दिन पहले ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है। हो सकता है कि माहौल को कुछ सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए ही केजरीवाल ने यह चिट्ठी लिखी हो। बहरहाल, वैक्सीन की कमी की शिकायतें लगभग हरेक जगह से मिल रही हैं और 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के लिए टीके लगवाना तकरीबन असंभव हो रहा है। यह स्थिति अभी बनी रहेगी, क्योंकि वैक्सीन की मांग बहुत है और आपूर्ति उसके मुकाबले काफी कम। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को पहले क्या सोचकर ऑर्डर दिए थे, यह नहीं मालूम, मगर उसके जो भी पूर्वानुमान थे, इस दूसरी लहर ने उसे तहस-नहस कर दिया है। अचानक संक्रमण के बढ़ने से लोग डर गए और टीका लगवाने दौड़ पड़े। बढ़ते दबाव में सरकार ने 18 से 44 की उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए जमीनी तैयारी नहीं थी। नतीजतन, एक किस्म की अफरातफरी का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हैं कि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने में दिक्कत आ रही है और अब तक देश की सिर्फ दो प्रतिशत जनसंख्या को दोनों खुराकें मिल पाई हैं। वैक्सीन का उत्पादन कंपनियां बढ़ाती हैं। उनका फॉर्मूला ज्यादा कंपनियों को मिल जाता है और एकाध नई वैक्सीन भी आती है, तब भी इसकी कमी दूर होने में दो-तीन महीने तो लग ही जाएंगे। ऐसे में, सरकार को चाहिए कि वह स्थिति का सही आकलन करे और उसके मुताबिक जनता को सही स्थिति बताते हुए टीकाकरण की योजना बनाए। यदि ऐसा न हुआ, तो अनिश्चय, अराजकता और संदेह का माहौल स्थिति को और खराब करेगा। इससे बचने की जरूरत है।

सच सामने आये

यूं तो दुनिया में बीते साल कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही यह बहस शुरू हो गई थी कि चीन से निकल कर दुनिया को लील रहा कोरोना वायरस प्राकृतिक है या फिर जैविक हथियार बनाने के मकसद से लैब में तैयार किया गया है। हर मौसम, हर जलवायु और हर भू-भाग में एक जैसा व्यवहार करने वाले विषाणु को कृत्रिम मानने वाले वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग भी रहा है। जिस तरह शुरुआत से ही चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने यहां जांच कराने में ना-नुकुर करता रहा, उसने इस शक को और गहरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को भी जिस तरह लंबे समय से रोका जाता रहा है, उसने विश्व बिरादरी की शंकाओं को विस्तार ही दिया है। अमेरिका भी लंबे समय तक ऐसे आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सार्वजनिक सभाओं में कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते रहे हैं। हाल ही में आस्ट्रेलियाई मीडिया के हाथ लगे चीनी सेना के कुछ खुफिया दस्तावेजों ने इन आशंकाओं को बल दिया है। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2015 से ही चीनी सेना कोरोना वायरस को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में काम करती रही है, जिसके पीछे धारणा यह रही है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वायरस युद्ध ज्यादा निर्णायक होगा। यहां सवाल यह भी उठता रहा है कि जिस चीन से यह कोरोना वायरस चला है, उसने इतनी जल्दी इससे कैसे मुक्ति पा ली। क्या उसने जैविक हमले की तर्ज पर इससे बचाव के लिये पहले से ही तैयारी कर रखी थी? आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संकट के इस भयावह दौर में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, चीन की आर्थिक प्रगति ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किये हैं, उसकी विकास दर अट्ठारह प्रतिशत तक पहुंची है। इस बीच उसका आर्थिक साम्राज्यवाद व महत्वाकांक्षी परियोजनाएं परवान चढ़ी हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस बात को जानने की जिज्ञासा है कि वास्तविकता क्या है और यदि चीन दोषी है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। निस्संदेह कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। अरबों-खरबों की क्षति के इतर पिछले डेढ़ साल में तैंतीस लाख लोग कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं, जिनमें ढाई लाख के करीब भारत के लोग हैं। लेकिन अभी भी यही सवाल बाकी है कि क्या कोविड-19 मानव निर्मित जैविक हथियार है? क्या वायरस वुहान की लैब से मानवीय गलती से लीक हुआ है? लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि यह महज जानवरों से वायरस के मानव तक संचरण का मामला था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कथित रूप से लीक हुए चीनी दस्तावेज के मीडिया में प्रकाशित होने के बाद इसकी संभावना पर रोशनी डाली है।

प्रोफेसर के नोट्स/दिलीप शाक्य

किसान की उपज

किसान ने पतवार संभाली और चम्बल की धार में नाव खेने लगा। हमने अपने प्रतिबिम्ब चम्बल के पानी में देखे तो हंसी आ गई। रात भर की पस्ती ने इस कदर रफ बना दिया था कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे थे। प्रोफेसर सिर्फ अपने चश्मे से ही प्रोफेसर लग रहे थे, लेकिन एक दूसरा सच भी सामने था। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आंते विद्रोह करने लगी थीं। कभी हम किसान को देखते कभी नाव पर लदे टमाटर, ककड़ी, मटर और अमरूद के टोकरों को।

किसान शायद भांप गया था। उसने हमसे कहा कि अगर भूख लगी हो तो हम सब्जियां और फल खा सकते हैं। हम इसी क्षण के इंतजार में थे। प्रोफेसर ने अमरूद और ककड़ियां खाने की सलाह दी। मैंने कुछ टमाटर भी खाए। हमें खाते देख शायद किसान की तलब भी जाग उठी थी। उसने कंधे से अपनी राइफल उतारकर अलग रखी और एक बोरी से तरबूज निकालकर हमें दे दिया। प्रोफेसर ने बोरी के पास रखे गड़से से तरबूज काटा जिसे हमने किसान के साथ बांटकर खाया। रात की थकान मिटने लगी थी। भोर की ठंडी हवा में सूर्य का पीला उजाला लहरों पर सलवटों-सा बिछा था। किसान ने बीड़ी सुलगा ली और बंडल आतिथ्यवश प्रोफेसर की ओर बढ़ा दिया। शेर छाप बीड़ी के बंडल पर शेर बना था और माचिस पर अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली की तस्वीर थी। प्रोफेसर को कुछ स्थानीय हिन्दी आती थी सो जल्दी ही वे किसान के साथ घुल-मिल गए। किसान बता रहा था कि उसका गांव किरारों का गांव है और उसका नाम घमंडीलाल है। मैंने नोटिस किया कि किसान राइफल और गड़से के साथ वैसा ही सहज दिख रहा था जैसा कोई कम्प्यूटर इंजीनियर की-बोर्ड और माउस के साथ दिखता है। प्रोफेसर ने पूछा कि ये सब्जियां और फल वह कहां ले जा रहा है? किसान ने बताया कि ये उसके अपने खेतों की उपज है। बिकने के लिए जा रही है। नदी के उस पार एक मेटाडोर आती है जो इन्हें तहसील की मंडी में ले जाती है। मेटाडोर वाला तोल के हिसाब से दाम देता है। आगे ये उपज किस दाम पर बिकती है इसके बारे में किसान को कुछ भी अनुमान नहीं था। प्रोफेसर मुझसे बोले- 'कुछ समझे? एक और बीमारी-फसलों की कालाबाजारी।'

कहीं भी ऑक्सीजन कम न हो

चंद्रकांत लहारिया

कोविड-19 की बीमारी में अब तक तीन तरीके बड़े स्तर के निदान संबंधी परीक्षणों में खरे उतरे हैं। पहला, डेक्सामेथासॉन का इस्तेमाल, दूसरा, खून पतला करने की दवाएं देना और तीसरा, ऑक्सीजन-सपोर्ट। (हां, यह सच है कि कोविड-19 में ऑक्सीजन एक इलाज या दवा है।) इसके अलावा बाकी दवाएं जैसे प्लाज्मा थेरेपी, इवेरमेक्टिन और रेमडेसिविर अधिकतर बड़े बहुद्देशीय निदान संबंधी परीक्षणों में प्रभावकारी नहीं पाए गए हैं। अलबत्ता, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन-सपोर्ट शुरुआत से ही एक मान्य तरीका रहा है। कोविड-19 के कुल मरीजों में से 15 से 20 फीसदी को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और उनमें से भी कुछ को ही ऑक्सीजन-सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए भारत में पहली लहर में जब सक्रिय मामले बढ़ने लगे, तब चिकित्सा-ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी। नतीजतन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति बनाई और स्वास्थ्य की स्थाई संसदीय समिति में इस पर चर्चा भी हुई। चिकित्सकीय-ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी, लेकिन मामला काबू में रहा।

मगर कोविड की इस दूसरी लहर में हालात हाथ से बाहर निकल गए। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि कोरोना की पहली लहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 10.5 लाख के करीब थी, लेकिन दूसरी लहर में यह संख्या 3.5 गुना तक बढ़ गई। आज देश भर में 37 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। फिर, यह भी देखा गया कि पिछली लहर की तुलना में इस बार आनुपातिक रूप से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। यानी, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी और ऑक्सीजन-सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों का अनुपात भी। इसका नतीजा यह हुआ कि चिकित्सकीय-ऑक्सीजन के लिए देश भर में बदहवासी का आलम पैदा हो गया। ऐसा नहीं है कि भारत में ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा। रोजाना 7,000-8,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम बना रहे हैं। कोविड-19 महामारी से पहले 30 फीसदी से भी कम ऑक्सीजन चिकित्सा-कार्य के लिए इस्तेमाल होती थी, शेष औद्योगिक कामों में खपत होती। लेकिन जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, तब दो मुख्य चुनौतियां उभरकर सामने आईं। पहली, औद्योगिक ऑक्सीजन सयंत्रों को चिकित्सकीय-ऑक्सीजन बनाने के लिए विशेष तैयारियां और समय की जरूरत थीं। और दूसरी, देश के कुछ ही राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जहां से जरूरतमंद राज्यों तक इसे लाने के लिए पर्याप्त विशेष टैंकर नहीं थे। निश्चित ही, इनसे निपटने के लिए पहले से योजना तैयार होनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं हो सका। महामारी एक राष्ट्रीय आपदा होती है, इसलिए इससे निपटने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। उसको इस बाबत समय पर योजना बनानी चाहिए थी और उसका बेहतर क्रियान्वयन भी करना चाहिए था। मगर राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकतीं। ऑक्सीजन का वितरण सही तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि राज्य अपने यहां कोरोना के आंकड़े दुरुस्त रखते और सही संख्या केंद्र को बताते। जिन-जिन राज्यों में कम मामले सामने आए, वहां नियमानुसार कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। पर चूंकि इन राज्यों में वास्तविक मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा थी, इसलिए शत-प्रतिशत आपूर्ति होने के बाद भी, असलियत में जमीनी स्तर पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी।

> क्षमता-निर्माण के साथ-साथ हमें अपने आसपास यह भी देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया गया।

देश में चिकित्सकीय-ऑक्सीजन की कमी का मसला एक और बड़े तथ्य की ओर इशारा करता है। राज्य सरकारें बेशक दावा करती हैं कि अपने-अपने अस्पतालों में वे मुफ्त में दवा और मरीजों की जांच की व्यवस्था करती हैं, मगर असलियत में ऐसा होता नहीं। मरीजों को न दवाएं मिलती हैं और न उनकी पर्याप्त जांच हो पाती है। देश भर में सरकारी अस्पतालों के बाहर निजी दवाई दुकानदार और नैदानिक केंद्रों की लंबी कतारें इसके सुबूत हैं। ऑक्सीजन भी एक दवाई है, और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति में भी वे सारी बातें इस पर लागू होती हैं, जो अन्य दवाओं पर लागू होती हैं। चूंकि निजी दवा दुकानदारों के पास भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया। अगर लोगों को आसानी से यह मिल जाता, तो शायद ऑक्सीजन की कमी का इतना हो-हल्ला नहीं मचता। इसलिए अगर हम इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें सरकारी स्वास्थ्य-तंत्र में दवा आपूर्ति और वितरण में आमूल-चूल सुधार करने पड़ेंगे। इसके फंड बढ़ाने होंगे, आपूर्ति-श्रृंखला को दुरुस्त करना होगा और इससे जुड़े लोगों को नियमित तौर पर प्रशिक्षण भी देना होगा। जाहिर है, बेहतर प्लानिंग और उचित वितरण की जरूरत है। यह सही है कि तीन-चार सप्ताह पहले अपने यहां जो परिस्थितियां थीं, उनमें कुछ सुधार हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नेशनल टास्क फोर्स गठित की है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी ऑक्सीजन की जरूरत, इस्तेमाल और वितरण पर सुझाव देना है। मगर हमें कोरोना की अगली लहर के लिए भी अभी से तैयार होना चाहिए। इसके लिए विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है। हमें अपने आसपास यह देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से ऑक्सीजन के वितरण को सुनिश्चित किया गया। महाराष्ट्र के नानदरबार के जिलाधिकारी ने छह-आठ महीने पहले ही अस्पतालों में ऑक्सीजन-प्लांट लगवा दिए थे। मुंबई नगर निगम ने भी लगभग यही किया, साथ ही नियंत्रण कक्ष बनाकर पूरे मुंबई को छह हिस्सों में बांट दिया व केंद्रीकृत व्यवस्था करते हुए सभी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। केरल ने भी फरवरी में ही ऑक्सीजन की कमी को भांप लिया था और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। नतीजतन, वहां भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर मारामारी नहीं हुई। आने वाले दिनों में नए ऑक्सीजन-प्लांट लगने, आपूर्ति-व्यवस्था में सुधार आने, ऑक्सीजन-कंसंट्रेटर के उपलब्ध होने और नए मरीजों की संख्या में कमी आने से स्थिति में सुधार होगा। हमने कोविड-19 की दूसरी लहर में चिकित्सकीय-ऑक्सीजन आपूर्ति में जिन कठिनाइयों, चुनौतियों, परेशानियों और नुकसान का सामना किया है, उनकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन इनसे सबक लेकर अगर केंद्र और राज्य सरकारें मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त जांच योजनाओं को सुदृढ़ करती हैं और उनको शब्दशः लागू करती हैं, तो हम यकीनन एक सभ्य और नैतिक समाज गढ़ पाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पतन की पराकाष्ठा

ज़िंदा इनसानों को नोचते कालाबाज़ारी गिद्ध

लक्ष्मीकांता चावला

हमारा देश भारत इस समय कोरोना महामारी से त्रस्त है। गली-गली में मौत की आहट और मृत्यु का तांडव है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां अंतिम संस्कार करने वाला भी कोरोना की भेंट चढ़ गया और परिवार समाप्त हो गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का यह समाचार है कि कुछ दिनों में चालीस से ज्यादा प्रोफेसर और कर्मचारी कोरोना के मुख में चले गए। अब सवाल यह है कि कोरोना महामारी से तो भारत त्रस्त है ही, पर यह जो कालाबाजारी हिंदुस्तान में चल रही है, इसकी चोट कोरोना से भी ज्यादा है। वैसे हमारा देश धर्म परायण देश है। ऋषियों-मुनियों ने यह शिक्षा दी है कि पराया धन मिट्टी के समान है। जब वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर ली तो शिष्यों ने पूछा कि कलियुग के प्राणी संभवतः इतना अध्ययन-मनन नहीं कर पाएंगे। सूत्र रूप में बताइए संदेश क्या है? उनका एक ही वाक्य था कि पर-उपकार ही पुण्य है और पर-पीड़ा पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्रीरामचरितमानस में यही लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहिं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। एक भी ऐसा धर्म नहीं है विश्व का जो भ्रष्टाचार को पाप न मानता हो। ऐसे संस्कारों वाले भारत वर्ष में कुछ लोग लोगों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, उन्हें आजकल समाचार पत्रों में ?गिद्ध कहा जाता है। गिद्ध तो मरे हुए पशु का शरीर खाते हैं, पर ये धन लोलुप व्यक्ति जिंदा मानव को लाश बना देते हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिन-रात वैज्ञानिक, डाक्टर संघर्ष कर रहे हैं। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग दूसरों की सेवा करते-करते अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली से यह समाचार मिलता है कि एक ही अस्पताल में बारह लोग आक्सीजन के अभाव में मौत के मुंह में चले गए। यह वह समय था जब दिल्ली के बहुत से व्यापारियों ने आक्सीजन ब्लैक में बेचकर सैकड़ों सिलेंडर सरकार और जनता की आंख से छुपाकर रखे थे। केवल दिल्ली में ही नहीं, अमृतसर से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में भी लोग तड़प-तड़प कर मरते रहे।

देश में केवल आक्सीजन का ही नहीं, प्राणरक्षक औषधियों का भी काला धंधा जोर-शोर से चला। तीन से पांच हजार रुपये का इंजेक्शन रेमेडिसिविर पचास हजार से एक लाख में बिका। नकली रेमेडिसिविर बनाने का धंधा भी देश में चल रहा है। कालाबाजारी को छिपाने के लिए सैकड़ों इंजेक्शन भाखड़ा नहर में भी बहाए। शायद कानून के पंजे से बचने के लिए। अभी तक यह तय नहीं हो सका, यह नकली हैं या असली। अफसोस यह है कि यह वही भ्रष्टाचार है, जिसे समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालते ही यह घोषणा की थी कि मैं न खाऊंगा, ना खाने दूंगा। पर आज तो ऐसा महसूस होता है कि इन अवैध धंधे करने वालों के बिना नेता अपना गुजारा नहीं कर सकते और चापलूसों की फौज खड़ी करके सच्चाई देखने से दूर भागते हैं। एक तरफ मौत बरस रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन में बेचारे सब्जी वाले की रेहड़ी ठोकर मारकर पलटा दी जाती है। दुकानों का दरवाजा बंद करके अपना काम कर रहे लोगों को भी निकालकर पीटने के समाचार फिल्लौर और अमृतसर से मिले हैं। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है कि गुरुग्राम से लुधियाना लाने के लिए एंबुलेंस का एक लाख बीस हजार रुपये किराया लिया जाता है। केवल एक नहीं, अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहां एक हजार का काम करने के लिए दस हजार लिए जा रहे हैं। दिल्ली और गुजरात के दो-चार प्रसिद्ध अमीर आक्सीजन की ब्लैक करते पकड़े गए हैं। होना तो यह चाहिए कि इन लोगों को केवल कालाबाजारी की सजा न दी जाए, अपितु जो लोग बिना आक्सीजन के मौत के मुंह में चले गए हैं, उनकी हत्या का दोष उन पर लगाया जाए। कोर्ट ने सही कहा था कि यह नरसंहार है जहां लोग बिना आक्सीजन के तड़प कर मर गए। यह भी कहा था कि इन लोगों पर हत्या का केस क्यों न बनाया जाए। कानून में चाहे कोई संशोधन करना पड़े, पर ऐसे लोगों को आजीवन सलाखों के पीछे तड़पते हुए छोड़ देना चाहिए, तभी शायद उनके साथ कुछ न्याय हो सकेगा जो प्राणवायु न मिलने से लाश बन गए और जिनके परिजन जिंदगी भर बिलखने के लिए रह गए।

दरअसल

राजनीतिक वायरस की वैक्सीन भी जरूरी

राजकुमार सिंह

हालांकि खुद सरकारी आंकड़े संदेह और सवालों के घेरे में हैं। फिर भी उन पर विश्वास करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो मान लीजिए कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उतार पर है। नहीं, इसमें दिग्भ्रमित सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सीमित संसाधनों वाले बेदम स्वास्थ्य तंत्र का भी इसमें कोई योगदान नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र और दिल्ली में नये कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी से दूसरी लहर में उतार का संकेत मिल रहा है तो यह लॉकडाउन का परिणाम है। देश की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई सरीखे विशाल महानगर समेत महाराष्ट्र में मार्च-अप्रैल में लगभग बेकाबू नजर आ रहे कोरोना से निपटने को लॉकडाउन का अलोकप्रिय निर्णय लेने का साहस पहली बार मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे ने दिखाया तो परिणाम भी सामने है। यह सुखद आश्चर्य है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना नियंत्रण के सफल प्रयासों के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की, वरना तो भाजपाई जोड़तोड़ को नाकाम कर जिन दिन से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा और उसकी केंद्र सरकार उनकी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घेराबंदी का कोई मौका नहीं चूकती।

कमोबेश यही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली अपूर्ण राज्य है, जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल ने सत्ता तो कांग्रेस से छीनी थी, लेकिन सत्ता पाने के भाजपाई मंसूबे एक नहीं, तीन बार नाकाम किये हैं। दुर्दिनों से गुजर रही कांग्रेस तो खिसियाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन भाजपा और उसकी केंद्र सरकार केजरीवाल की घेराबंदी के लिए जैसे हर समय मौके की तलाश में रहती हैं। बेशक इसके लिए अधूरे राज्य के कुछ ज्यादा ही बड़बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन भाजपा का तो केजरीवाल को कोसना ही जैसे एकसूत्री कार्यक्रम रह गया है। माना कि महाराष्ट्र और दिल्ली, दोनों ही जगह भाजपा विपक्ष में है। यह भी कि सरकार के कामकाज की निगरानी और खामियों को उजागर करना सजग-सक्रिय विपक्ष का अधिकार ही नहीं, संवैधानिक-लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है, पर क्या कोरोना सरीखे अभूतपूर्व आपदाकाल में भी किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल को विपक्ष की परंपरागत मानसिकता और छवि में ही कैद रहना चाहिए? निश्चय ही अकेली भाजपा इस विरोधी ग्रंथि की शिकार नहीं है। एक सप्ताह देर से लॉकडाउन लगाने के बाद ही सही, हरियाणा सरकार ने बीपीएल मरीजों के लिए होम आईसोलेशन पर 5 हजार रुपये, निजी अस्पताल में 7 दिन इलाज के लिए 35 हजार रुपये देने, जरूरतमंदों को घर-घर ऑक्सीजन की डिलीवरी और अब गांवों में भी घर-घर कोरोना जांच तथा कोरोना से जंग में सेना एवं उद्योग जगत की मदद लेने जैसी जो पहल की हैं, वे तो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय होनी चाहिए, लेकिन राज्य में विपक्षी दलों को कोरोना नियंत्रण में सरकार की नाकामी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा।

पिछले साल कोरोना की आहट के साथ ही 50 दिन लंबा लॉकडाउन लगाकर सभी की आलोचना का पात्र बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अब कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद राज्यों को यह नसीहत देते नजर आते हैं कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प ही समझें तो कुछ लोग उनसे सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास बेकाबू कोरोना के नये मरीजों को इलाज दे पाने की न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं नजर आ रहीं, गंभीर मरीज अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तब संक्रमण की इस रफ्तार पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के अलावा उपाय ही क्या शेष रह जाता है? बेशक हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला कुछ देर से लिया गया, लेकिन अब नये कोरोना केस के घटते आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन ही इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध जंग में हमारा सबसे कारगर हथियार है। बेशक एक-सवा साल के खौफनाक अनुभव के बाद भी कोरोना से जंग में हमारे संसाधनों-विकल्पों की यह सीमितता हमारी अदूरदर्शिता और गलत प्राथमिकताओं का ही प्रमाण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि कोरोना की आहट से लेकर दूसरी लहर की स्पष्ट चेतावनियों के बीच हमारे यहां स्वास्थ्य सेवाओं का क्या और कितना विस्तार हुआ? बढ़ते संकट के बीच भी कोरोना वैक्सीन कूटनीति और ऑक्सीजन निर्यात क्यों जारी रहा? ऐसे सवालों की फेहरिस्त लंबी बन सकती है, जो केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारों से भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जब कोरोना काल बनकर मानवता पर टूट रहा है, तभी इस पर राजनीति की जाये, दोषारोपण का खेल खेला जाये?

दुर्भाग्यवश हो यही रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भाजपा को कुछ सही होता नहीं दिख रहा तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस को भी कोरोना से जंग में सिर्फ काहिली ही नजर आ रही है। कोरोना से जंग में चौतरफा नाकामी के बावजूद राजनीतिक दलों का यह रवैया मानवीय संवेदनाओं के बजाय दलगत स्वार्थों से ज्यादा प्रेरित है। कहना नहीं होगा कि इस राजनीतिक वायरस की वैक्सीन भी बहुत जरूरी है। विदेशी ही नहीं, स्वदेशी मीडिया की भी सचित्र रिपोर्टों के बाद यह तो साफ है कि कोरोना काल में सरकारी आंकड़े सच बता कम रहे हैं, छिपा ज्यादा रहे हैं। यह भी कि बार-बार आगाह किये जाने के बावजूद कोरोना को गांवों तक फैलने से नहीं रोका जा सका है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतारें हैं तो अंतिम संस्कारों के लिए टोकन बंट रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से तो नदियों में भी लाशें बहती मिल रही हैं। लेकिन हमारी सरकारें अपना समय और ऊर्जा हालात पर नियंत्रण से ज्यादा मृतकों के आंकड़े छिपाने तथा नदियों में बहती लाशों को दूसरे राज्यों की बताने में लगा रही हैं। निश्चय ही सरकारों का यह संवेदनहीन रवैया बदलना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सत्ता का चरित्र आसानी से नहीं बदलता। इसलिए राजनीतिक दलों को तो कम से कम इस आपदाकाल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी-निभानी चाहिए। मीडिया में जो भी दावे किये जायें, पर कोरोना से उत्पन्न गंभीर संकट के बीच पीड़ितों-प्रभावितों को जरूरी मदद में राजनीतिक दलों की भूमिका जमीन पर ज्यादा नजर नहीं आती। कोरोना के विस्तार और गहराते संकट के बीच सरकारी तंत्र की सीमाएं हम सभी देख रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को चाहिए कि सोशल मीडिया -मीडिया में एक-दूसरे पर दोषारोपण का अपना प्रिय खेल बाद के लिए छोड़ कर फिलहाल जमीन पर उतरें, जनता के बीच जायें। जाहिर है, पीड़ितों को चिकित्सकीय सुविधा राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता नहीं दे सकते, पर जरूरी चीजों में मदद का हाथ अवश्य बढ़ा सकते हैं। सवा साल बाद भी कोरोना से बचाव के प्रति जनता में जरूरी जागरूकता नहीं दिखती तो यह सरकार से ज्यादा समाज की नाकामी है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका-चीन के बढ़ते तनाव से Tesla की इस योजना को लग सकता है झटका

बिजनेस डेस्क: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला चीन के शंघाई में स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विस्तार योजना को रोक सकती है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) शंघाई में अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबल एक्सपोर्ट हब (GEH) बनाना चाहती थी। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने यह फैसला अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से लिया है।

अब भी काफी टैक्स

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से इलेक्ट्रिक कार के आयात पर मौजूदा कर के साथ 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। यह शुल्क अभी चालू है। इसके बाद इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी इ़द्दइइइ ने चीन में उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं में कटौती की है। टेस्ला ने इससे पहले अपने चीनी निर्मित एंट्री लेवल मॉडल 3 के एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करने की प्लानिंग की थी जिसमें अमेरिका भी शामिल था।

शेयरों पर दिखा असर

मंगलवार को प्री मार्केट ट्रेडिंग में टेस्ला के शेयर 7 फीसदी गिरकर कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार खुलने के बाद इसमें कुछ भरपाई की और यह करीब 1 फीसदी कमजोर चल रहा था। टेस्ला ने इससे पहले योजना बनाई थी कि चीन में बनी हुई एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 को वह दुनिया के अधिक से अधिक बाजार में बेचने के लिए अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाएगी। कंपनी अमेरिकी बाजारों में भी एंट्री लेवल मॉडल 3 को बेचना चाहती थी। इस समय टेस्ला चीन में बनी मॉडल 3 को यूरोप में बेच रही है, इसके साथ ही जर्मनी में भी एक प्लांट लगा रही है।

प्रोडक्शन बढ़ाने की थी योजना

चीन के शंघाई में बनी टेस्ला की फैक्ट्री सालाना 5,00,000 इलेक्ट्रिक कार बनाने में सक्षम है। इस समय मॉडल 3 और मॉडल वाई कार की इस फैक्ट्री में 450,000 यूनिट सालाना बनाई जा रही है। इस साल मार्च में ही टेस्ला (Tesla) ने शंघाई में अपनी यूनिट के पास बिक रहे प्लॉट की बोली से हाथ खींच लिया था। कंपनी ने कहा था कि चीन में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की इसकी अब कोई योजना नहीं है।

भारत की वृद्धि दर 2022 में 10.1% रहने का अनुमान, लेकिन 2021 आउटलुक अत्यधिक नाजुकः संयुक्त राष्ट्र

बिजनेस डेस्कः संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2022 में 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वह उस समय दुनिया के प्रमुख देशों में तीव्र वृद्धि दर हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि, उसने कहा कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी काफी नाजुक दिख रहा है। इसका कारण देश में महामारी का तेजी से फैलना है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना (डब्ल्यूईएसपी) रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा में कहा कि भारत की वृद्धि दर 2022 में 10.1 प्रतिशत रहेगी। यह जनवरी में जारी रिपोर्ट में 5.9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले लगभग दोगुनी है। इसमें कहा गया है कि 2022 में 10.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र गति से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा और इस मामले में चीन से भी आगे होगा। रिपोर्ट में चीन की वृद्धि दर 2022 में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जो 2021 में 8.2 प्रतिशत की संभावना से कम है। अद्यतन की गई मध्यावधि रिपोर्ट में भारत की वद्धि दर 2021 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि 2020 में इसमें 6.8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। मध्यावधि समीक्षा में भारत को लेकर जताए गए अनुमान पूर्व के अनुमान से बेहतर हैं। इससे पहले, जनवरी में जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया था। वहीं 2021 और 2022 में इसमें क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की संभावना जताई गई थी।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 471 अंक लुढ़का, निफ्टी 14,700 से नीचे

मुंबईः

शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई जिससे सेंसेक्स 471 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मिश्रित रुख और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और रिलायंस जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 471.01 अंक यानी 0.96 प्रतिशत लुढ़कर 49 हजार अंक से नीचे 48,690.80 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 154.25 अंक यानी 1.04 प्रतिशत की गिरावट लेकर 14,696.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक 3 प्रतिशत का नुकसान इंडसइंड बैंक को हुआ। इसके अलावा एचयूएल, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट रही। दूसरी तरफ, टाइटन, मारुति, पावरग्रिड, एसबीआई और एनटीपीसी लाभ में रहने वाले शेयरों में शामिल हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर के अनुसार उपभोक्ता जिंसों की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक बाजार में ब्याज दरें और बांड प्रतिफल बढ़ने की चिंता में सूचकांक नीचे आए। उन्होंने कहा, ''सभी प्रमुख सूचकांक समेत कीमती धातु गिरावट लेकर बंद हुए जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और मीडिया शेयरों में तेजी बनी रही। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई और हांगकांग लाभ में रहे जबकि टोक्यो और सोल में गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख बाजारों में मध्य कारोबार में मिश्रित रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकर 68.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

लॉकडाउन के बावजूद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में सिर्फ 1.5 प्रतिशत घटी

लंदनः

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लागू किए गए सख्त लॉकडाउन के बावजूद 2021 की पहली तिमाही में सिर्फ 1.5 प्रतिशत घटी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बुधवार को बताया कि जब लॉकडाउन में थोड़ी राहत देने की शुरुआत हुई, तो मार्च में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रही। पहली तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि कारोबारियों और उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ाकर लॉकडाउन की बाधाओं को कम करने का प्रयास किया। इससे पहले 2020 की दूसरी तिमाही में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो अर्थव्यवस्था में करीब 20 प्रतिशत संकुचन आया था।

कोविड टीकाकरण अभियान- NTPC ने 70 हजार से अधिक कर्मचारियों, आश्रितों को टीका लगवाया

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बुधवार को कहा कि उसने अपने 70 हजार से अधिक कर्मचारियों, श्रमिकों और उनके पारिवारिक सदस्यों को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है। एक बयान के मुताबिक देश भर के सभी संयंत्रों में बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें एनटीपीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी सहयोगी और उनके आश्रित भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 70,000 से अधिक कर्मचारियों, श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को टीके लगवाएं हैं। बयान में आगे कहा गया कि संबंधित राज्य प्रशासन के साथ मिलकर एनटीपीसी केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी ने सुनिश्चित किया है कि उसके अग्रिम पंक्ति में रहकर काम करने वाले कर्मचारियों, मौजूदा और सेवानिवृत सभी को टीका लगाया जाए। इसमें 60 वर्ष से ऊपर की आयु का सेवानिवृत्त स्टाफ और 45 वर्ष की उम्र से ऊपर के वर्तमान में काम कर रहा स्टाफ भी शामिल है। कंपनी ने 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग में भी पात्र कर्मचारियों को टीका लगाने का काम शुरू किया है। वक्तव्य के मुताबिक कंपनी के देशभर में फैले 72 स्थानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संयुक्त उद्यम और अनुषंगी कंपनियां भी शामिल हैं। टीकारण अभियान के साथ ही एनटीपीसी ने कोविड- 19 से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिये एक कार्यबल का भी गठन किया है जो कि सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा है और कोविड मरीजों के लिए समन्वय का काम कर रहा है।

Google Pay की मदद से दूसरे देशों में कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, जानें कैसे

बिजनेस डेस्कः

गूगल पे यूजर्स के लिए खुशखबरी है। गूगल ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सुविधा की शुरुआत की है। अब आप इसके जरिए एक देश से दूसरे देशों में भी पैसे भेज सकते हैं। हालांकि अभी यह सुविधा केवल अमेरिकी ग्राहकों के लिए है। पर इस साल के अंत तक दुनिया के 80 देशों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। गूगल ने इस अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए रेमिटेंस फर्म यानी पैसे भेजने वाली कंपनी वाइज और वेस्टर्न यूनियन के साथ भागीदारी की है। इसके जरिए वह आपके पैसों को दूसरे देशों में भेजेगा। गूगल ने कहा कि अमेरिका में गूगल पे के ग्राहक अब गूगल पे ऐप के जरिए भारत और सिंगापुर में पैसे भेज सकते हैं। अमेरिका में काफी भारतीय रहते हैं और इसलिए वहां से इसकी शुरुआत की गई है।

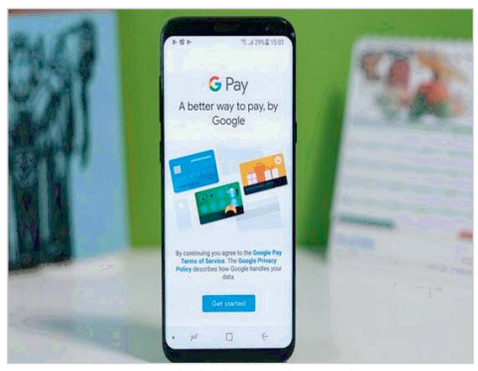

भारत एक बड़ा बाजार है

आबादी के लिहाज से गूगल को भारत एक बड़ा बाजार मानता है। गूगल ने दुनिया के 470 अरब डॉलर के इस रेमिटेंस यानी पैसे भेजने के बाजार में टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़े हिस्से पर काबिज करने की योजना बना रहा है। यह अपनी फाइनेंशियल सेवाओं को बढ़ाना चाहता है। यह डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में एक पैठ बनाना चाहता है। लंदन की वाइज ने 2011 में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा शुरू की थी। यह सबसे सस्ती और आसान सुविधा है। हालांकि इस सेक्टर में वेस्टर्न यूनियन मनी अभी भी लीडर है। इसके पास फिजिकल लोकेशन का एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है।

बड़े बाजार की तलाश में गूगल

गूगल पे के साथ इन दोनों की भागीदारी से एक बड़ा बाजार मिलेगा। गूगल पे के 40 देशों में 15 करोड़ ग्राहक हैं। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में इस समय ऑन लाइन पेमेंट पर फोकस है। ग्राहक भी इसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक, हालांकि 2019 में प्रवासी लोगों द्वारा भेजे जाने वाले पैसों में 14 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थितियां कमजोर थीं और जिन देशों में प्रवासी लोग रहते हैं, वहां उनके रोजगार में कमी आई थी।

ज्यादा देशों में पहुंचने की योजना

कोविड-19 के बाद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। गूगल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर जोश वुडवार्ड ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस साल के लिए उन देशों तक पहुंचना है, जहां तक वेस्टर्न यूनियन और वाइज का नेटवर्क है और जहां तक वे सपोर्ट कर सकते हैं। गूगल की इस नई रणनीति ने अन्य टेक कंपनियों को भी इस सेक्टर में उतरने के लिए एक आइडिया दे दिया है। यह एक तरह से सभी ग्राहकों के लिए वित्तीय जरूरतों का वन स्टॉप शॉप है।

संतुलित व्यापार व्यवस्था के पक्ष में है भारतः पीयूष

नई दिल्लीः

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत व्यापार और निवेश संरक्षण पर एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के पक्ष में है। गोयल ने विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक व्यापार सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) एक संतुलित समझौता नहीं था क्योंकि इससे भारत के किसानों, छोटे उद्योगों- एमएसएमई, डेयरी उद्योग को नुकसान होगा और इसलिए भारत के लिए आरसीईपी में शामिल नहीं होना एक समझदारी थी। उन्होंने कहा कि भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों के लोगों के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए व्यापार और निवेश वार्ता और संभावित संभावनाओं के लिए तत्पर है। भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों और संस्थाओं के साथ लोकतंत्र, पारदर्शिता, कानून का शासन, अदालतों की स्वतंत्रता, निवेश के नियमों, आदि के संदर्भ में समान है, इसके अलावा, इन देशों के साथ भारतीय व्यापार संतुलित है। गोयल ने कहा कि हम निश्चित रूप से कुछ देशों के सीमित एजेंडे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार व्यवस्था, सब्सिडी व्यवस्था और लाभ जो विकसित दुनिया लाभ ले रही है, उसका विश्व व्यापार संगठन में अधिक संवेदनशीलता और अधिक ईमानदारी के साथ समाधान किया जाना है। उन्होंने कहा कि विश्व के एजेंडे को विश्व व्यापार संगठन की वास्तविक भावना में निष्पक्ष, न्यायसंगत रूप से तैयार करना होगा। कोविड-19 के मुद्दे पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज महामारी की दूसरी लहर का अनुभव कर रहा है और इस लहर की भयावहता गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत निर्बाध रूप से महामारी से लड़ रहा है। सरकार महत्वपूर्ण आपूर्ति की खरीद, राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का वितरण और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने रेलवे की 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' शुरू करने के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे निरंतर प्रयासों के साथ, हम जल्द ही इस वैश्विक चुनौती को पार कर पाएंगे और मजबूत बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत लचीला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनना चाहता है। महामारी की पहली लहर के दौरान भी, देश ने अपनी सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा किया।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को रुपये में गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आठ पैसे गिरकर 73.42 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.51 पर खुला और इसने दिन के कारोबार के दौरान 73.39 से 73.51 के दायरे में कारोबार करता रहा। अंत में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 73.42 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 73.34 के मुकाबले आठ पैसे की गिरावट दिखाता है। वहीं इसी बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 फीसदी बढ़कर 90.26 पर पहुंच गया हालांकि, डॉलर की कमजोरी और बेहतर वृहद आर्थिक आंकड़ों की उम्मीद ने गिरावट पर कुछ रोक लगायी।

रुचि सोया इंडस्ट्रीज खरीदेगी पतंजलि नेचुरल बिस्कुट, 60 करोड़ में होगी डील

बिजनेस डेस्कः

रूचि सोया इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को पतंजलि नेचुरल बिस्कुट प्राइवेट लि. (पीएनबीपीएल) के कारोबार को 60.02 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 10 मई को पतंजलि बिस्कुट के साथ व्यापार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। यह अधिग्रहण अगले दो महीने में पूरा होगा। रूचि सोया ने कहा, ''व्यापार हस्तांतरण समझौते के तहत अधिग्रहण की रकम 60.02 करोड़ रुपए तय की गई है। अधिग्रहण की यह रकम घटती बिक्री के आधार पर की गई है। उसने कहा कि अधिग्रहण की रकम दो किश्तों में दी जाएगी। जिसमें 15 करोड़ रुपए समझौता होने की तिथि या उससे पहले दिए जाएंगे, जबकि शेष 45.01 करोड़ रुपए का भुगतान समझौता होने के 90 दिनों में होगा। कंपनी ने कहा कि वह और पतंजलि बिस्कुट एक गैर-प्रतिस्पर्धी समझौते पर भी सहमत हुए हैं। जिसके तहत पीएनबीपीएल और उसके संबंधित सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में बिस्कुट के किसी भी प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि रुचि सोया कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी थी जिसे 2019 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने खरीद लिया था। पीनीबीएल ने वित्त वर्ष 2019-20 में 448 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

5G नेटवर्क के ट्रायल से चीनी कंपनियों को दूर रखना भारत सरकार का अच्छा फैसलाः अमेरिका

बिजनेस डेस्कः

भारत द्वारा हाल में चीनी कंपनियों हुवावेई और जेडटीई के बिना 5जी परीक्षणों को करने के फैसले को अमेरिका ने एक संप्रभु निर्णय कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका उन उपकरणों के साथ नेटवर्क स्थापित करने के खतरों को लेकर अत्यधिक चिंतित है, जिन्हें चीन द्वारा बाधित या नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को कहा, यह भारत सरकार द्वारा एक संप्रभु निर्णय था, इसलिए, हमारा मानना है कि इस बारे में आपको भारत सरकार से ही कोई टिप्पणी लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन मैं अधिक व्यापक रूप से कह सकता हूं कि यह सही है कि हम ऐसे उपकरणों पर आधारित नेटवर्क के खतरों को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइन) नियंत्रण या बाधित कर सकता है।

चीन के योगदान से देश की सुरक्षा को खतरा

उन्होंने कहा कि हुवावेई या जेडटीई जैसे गैर-भरोसेमंद दूरसंचार आपूर्तिकर्ताओं को अनुमति देने में राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता और मानवाधिकारों से जुड़े जोखिम शामिल हैं। दूरसंचार विभाग ने 4 मई को 5जी परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दी थी, हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करेगी। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएनएल के आवेदनों को मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का उपयोग नहीं कर रही है।

चीन ने जताया अफसोस

दूरसंचार विभाग ने 5जी परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गीयर विनिर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी-डॉट और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां 5जी परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगी। दूरसंचार विभाग का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार देश में शुरू होने वाली 5जी दूरसंचार सेवाओं में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने से रोक सकती है।

मोबाइल उत्पादन पर कोविड की दूसरी लहर का असर, 50% घटी मैन्युफैक्चरिंग

बिजनेस डेस्कः

स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन, सेमीकंडक्टर में कमी और कारखानों के कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण होने की वजह से अप्रैल तथा मई में मोबाइल फोन के विनिर्माण और बिक्री में खासी कमी आई है। इस वजह से अप्रैल-जून तिमाही इन कंपनियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गई है। कई मोबाइल फोन कंपनियों के प्रमुखों ने यह बात कही। लावा इंटरनेशनल के सह-संस्थापक एसएन राय और माइक्रोमैक्स के सह-संस्थापक राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि देश भर में कोरोना संक्रमण तेज होने के कारण अप्रैल-मई में मोबाइल फोन का विनिर्माण करीब 50 फीसदी घटा है। राय कहते हैं, जून तिमाही में स्थिति वाकई चुनौती भरी है। हमारी जैसी कुछ कंपनियां अप्रैल में भी उत्पादन जारी रख पाईं क्योंकि हमारे पास पुर्जों का कुछ स्टॉक बचा था। मगर सभी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं है। संक्रमण फैलने और लॉकडाउन होने के कारण मई का महीना सभी के लिए खराब रहा है। उद्योग की बात करें तो कारोबार को करीब 50 फीसदी चपत लगी है। माइक्रोमैक्स के अग्रवाल ने कहा, जून तिमाही कठिन रहने वाली है क्योंकि माहौल खराब है। संक्रमण की दूसरी लहर खरीदारों का हौसला कमजोर हुआ है। लॉकडाउन हटने के बाद इसमें धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। आईडीसी इंडिया के शोध निदेशक नवकेंद्र सिंह ने कहा, %2021 कैलेंडर वर्ष में सुधार उतना नहीं होगा, जितने की उम्मीद पहले लगाई गई थी। दूसरी लहर का प्रभाव और तीसरी लहर की आशंका का असर लंबे समय तक रह सकता है। सिंह ने कहा कि 2021 में स्मार्टफोन बाजार की सालाना वृद्धि एक अंक में रहेगी। पहले दो अंकों में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने चेताया कि गैर-जरूरी खर्च में कमी, आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव और पुर्जों की कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा है, जिससे आने वाली तिमाहियों में भी दबाव देखा जा सकता है। राय ने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद दो-तीन हफ्ते नरमी रहेगी और उसके बाद उत्पादन शुरू हो सकता है लेकिन बेहतर सुधार के लिए महीनों इंतजार करना पड़ सकता है।

कैडिला हेल्थकेयर की इकाई भारत केंद्रित पशु स्वास्थ्य कारोबार 2,921 करोड़ रुपए में बेचेगी

नई दिल्लीः

कैडिला हेल्थकेयर ने बुधवार को कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जायडस एनिमल हेल्थ एंड इनवेस्टेंट ने अपने पशु स्वास्थ्य कारोबार की बिक्री के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। यह बिक्री मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट की अगुवाई वाले गठजोड़ को 2,921 करोड़ रुपए में की जाएगी।कैडिला हेल्थकेयर ने एक बयान में कहा कि इस गठजोड़ में कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और रेरा एंटरप्राइजेज शामिल हैं और इसने एक एसपीवी के माध्यम से जेनेक्स एनिमल हेल्थ इंडिया के नाम से खरीद समझौता किया है। बयान में कहा गया कि इस पशु देखभाल कारोबार जायडस एएच का फोकस भारत और कुछ अन्य देशों पर था। कंपनी ने बताया कि यह बिक्री नकद मुक्त और ऋण मुक्त आधार पर कुल 2,921 करोड़ रुपए में की जाएगी, हालांकि यह सौदा अभी कई शर्तों के अधीन है।बयान में कहा गया कि जायडस एएच लगभग 700 लोगों को रोजगार देता है और हरिद्वार में इसका एक विनिर्माण संयंत्र है। कैडिला हेल्थकेयर ने कहा, सौदे में अचल संपत्ति, चल संपत्ति, रसद, ब्रांड और अमूर्त संपत्ति, अनुबंध, लाइसेंस और अनुमतियां, व्यापार रिकॉर्ड, कर्मचारियों के साथ कर्मचारी लाभ निधि, बीमा पॉलिसियां, अन्य संपत्ति और ग्रहण योग्य देनदारियों का हस्तांतरण शामिल है। बयान में बताया गया कि यह सौदा कुछ शर्तों के अधीन है और इसके लिए सभी वैधानिक और अन्य मंजूरियां ली जानी हैं। उम्मीद है कि सौदा 90 दिनों के भीतर पूरा होगा। कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा, मल्टीप्लेस और इसके साझेदार कारोबार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें यकीन है कि जायडस एएच उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक और सीईओ रेणुका रामनाथ ने कहा, हम डा.अरुण अत्रे के नेतृत्व में जायडस एएच की बेहतरीन टीम का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं, और यह एक ऐसे कारोबार में निवेश है जो पशु स्वास्थ्य समाधान के जरिए किसानों को उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद कर रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एकजुट हो गए तो आईपीएल खेलेंगे : पीटरसन

लंदन । केविन पीटरसन का मानना है कि इंग्लैंड के शीर्ष क्रिकेटर अगर वर्तमान में निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैच सितंबर में होने की दशा में इसमें खेलने को लेकर एकजुट हो गए तो देश के क्रिकेट बोर्ड को उनकी सुननी ही होगी। ईसीबी के क्रिकेट निदेशक एशले जाइल्स ने संकेत दिया था कि उनके अनुबंधित क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में व्यस्त रहने के कारण आईपीएल नहीं खेल सकेंगे। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन के अलावा जोफा आर्चर, जोस बटलर और बेन स्टोक्स जैसे सितारा खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। पीटरसन ने ट्वीट किया- यह देखना रोचक होगा कि ईसीबी आईपीएल के बाकी मैच होने की दशा में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं देने के इस मामले से कैसे निपटता है। आईपीएल बायो बबल में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद लीग चार मई को स्थगित कर दी गई थी।

कभी कभी धोनी के मार्गदर्शन को मिस करता हूं : कुलदीप यादव

नई दिल्ली। गेंदबाज कुलदीप यादव का मानना है कि वह पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के उस मार्गदर्शन को मिस कर रहे हैं, जोकि उन्हें धोनी से मिलता था।

धोनी और कुलदीप 2019 के आखिर से ही भारत के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं। हालांकि पिछले साल की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं।कुलदीप ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा, कभी-कभी मैं माही भाई का गाइडेंस मिस करता हूं, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव था। वह विकेट के पीछे से हमें गाइड करते थे, लगातार चिल्लाते रहते थे। हम उनका अनुभव मिस करते हैं। ऋषभ पंत अब उनकी जगह हैं, वह जितना खेलते जाएंगे वह भविष्य में हमें उतना ज्यादा इनपुट दे पाएंगे। मुझे हमेशा लगता है कि हर गेंदबाज को एक पार्टनर चाहिए होता है, जो दूसरे छोर से रिस्पॉन्ड करे। कुलदीप ने 2019 में 23 वनडे खेले थे जबकि 2020 और 2021 में उन्होंने अब तक केवल सात ही वनडे मैच खेले हैं। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपना आखिरी मैच जुलाई 2019 में खेला था। कलाई के स्पिनर ने कहा, जब माही भाई टीम में थे, तब मैं और युजवेंद्र चहल खेल रहे थे। जब से माही भाई गए हैं मैंने और चहल ने साथ में मैच नहीं खेले। मुझे गिने-चुने मैच ही खेलने का मौका मिला। मैंने कुल 10 मैच खेले होंगे, जिसमें मैंने हैट्रिक भी ली। अगर आप मेरे प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, तो मेरा प्रदर्शन ठीक था।

बार्सिलोना को नहीं मिली बढ़त, लेवांटे के खिलाफ ड्रा खेला

मैड्रिड ।

बार्सिलोना ने दो गोल की बढ़त के बावजूद लेवांटे के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच 3-3 से ड्रा खेलकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में शीर्ष पर पहुंचने का एक और मौका गंवा दिया। बार्सिलोना एक समय 2-0 और फिर 3-2 से आगे था लेकिन वह अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाया जबकि उसका हर खिलाड़ी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि जीत से उनकी टीम शीर्ष पर पहुंच जाएगी। यह मैच ड्रा होने से बार्सिलोना अब एटलेटिको मैड्रिड से एक अंक पीछे दूसरे स्थान पर है। एटलेटिको ने उससे एक मैच कम खेला है। एटलेटिको का अगला मैच पांचवें नंबर के रीयाल सोसिडाड से होगा। बार्सिलोना मौजूदा चैंपियन रीयाल मैड्रिड से एक अंक आगे हैं जिसे गुरुवार को 10वें नंबर के ग्रेनाडा से भिडना है। इन मैचों के बाद केवल दो दौर के मैच ही बचे रहेंगे। लियोनेल मेस्सी ने 25वें मिनट में बार्सिलोना के लिये पहला गोल किया जबकि पेड्रो गोंजालेज ने 34वें मिनट में बढ़त दोगुनी करके अपनी टीम को मध्यांतर तक 2-0 से आगे कर दिया था। लेवांटे ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। गोंजालो मलेरो (57वें) और जोस लुईस मोरेल्स (59वें मिनट) ने दो मिनट के अंदर दो गोल करके लेवांटे को बराबरी दिला दी। ओसमाने डेम्बले ने 64वें मिनट में बार्सिलोना को फिर से बढ़त दिलाई लेकिन सर्जियो लियोन ने 83वें मिनट में लेवांटे की तरफ से बराबरी का गोल दाग दिया। अन्य मैचों में अलावेस ने एल्ची को 2-0 से जबकि ओसासुना ने कैडिज को 3-2 से हराया।

इटालियन ओपन : ओसाका दूसरे दौर में बाहर

रोम।

वर्ल्ड नंबर-2 जापान की नाओमी ओसाका यहां जारी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड नंबर 31 अमेरिका की जेसिका पेगुला ने पहले राउंड में बाई पाने वाली ओसका को दूसरे राउंड में 7-6 (7-2) 6-2 से मात दी। 23 साल की ओसाका को हराकर पेगुला ने अपने करियर की अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ओसाका को मैड्रिड ओपन में भी दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच, मैड्रिड ओपन के फाइनल में हारने वाली वर्ल्ड नंबर-1 आस्ट्रेलिया की एश्लेग बार्टी ने कजाखिस्तान की यारोसलावा श्वेदोवा को 6-4 6-1 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

राफेल नडाल की दो टूक- तोक्यो ओलंपिक में खेलना सुनिश्चित नहीं

रोम ।

दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रफेल नडाल उन टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जो तोक्यो ओलंपिक में खेलने को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं। इटालियन ओपन में खेल रहे नडाल से जब एक साल के लिए स्थगित किए गए ओलंपिक में खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- अभी मैं नहीं जानता। ईमानदारी से कहूं तो मैं स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं अपने कैलेंडर के बारे में नहीं जानता। नडाल ने कहा- सामान्य समय में ओलंपिक खेल हमेशा मेरी मुख्य प्राथमिकता होते थे। मौजूदा समय में ओलंपिक अब भी प्राथमिकता है लेकिन चीजें बदल गई हैं। हम लगभग डेढ़ साल से इस महामारी से जूझ रहे हैं और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं फैसला थोड़े समय को ध्यान में रखकर लूंगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक 2020 को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नडाल ने कहा- वर्तमान परिस्थितियों में मैं नहीं जानता। देखते हैं कि अगले दो महीनों में क्या होता है। लेकिन मुझे अपना कार्यक्रम व्यवस्थित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा- मैं अगले छह महीने नहीं बल्कि कुछ सप्ताह का ही कार्यक्रम बना रहा हूं। यह सब कुछ बदलती चीजों पर निर्भर करेगा और मेरा शरीर तथा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है क्योंकि मैं पहले ही 35 बरस का हो चुका हूं। नडाल ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में एकल का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पांच साल पहले रियो डि जेनेरियो ओलंपिक में युगल का स्वर्ण पदक हासिल किया था। नडाल से पहले सेरेना विलियम्स ने कहा कि कोरोना वायरस प्रोटोकाल के कारण यदि उनके लिए अपनी तीन साल की बेटी को तोक्यो ले जाना संभव नहीं होगा तो वह ओलंपिक में भाग नहीं लेगी। जापान के केई निशिकोरी और नाओमी ओसाका भी खेलों के आयोजन पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं।

संक्षिप्त समाचार

महिला हॉकी टीम की फारवर्ड लालरेमसियामी ने कहा, हमें अधिक गोल करने होंगे

बेंगलुरू। भारतीय महिला हॉकी टीम की फारवर्ड लालरेमसियामी ने कहा कि जर्मनी के हाल के दौरे से मिली सीख के आधार पर टीम ओलंपिक खेलों से पहले अपने गोल स्कोरिंग दर में सुधार करने की कोशिश करेगी। भारत की तरफ से 64 मैच खेलने वाली लालरेमसियामी ने कहा कि फरवरी-मार्च के जर्मनी दौरे से उन्हें अपनी कमजोरियों का पता करने में मदद मिली। लालरेमसियामी ने कहा- जर्मनी का दौरा हमारे लिए कड़ा रहा लेकिन हमने उस दौरे में जो चार मैच खेले उनमें हमें अपने खेल के बारे में कई चीजें सीखने का मौका मिला। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि जर्मनी के दौरे में हमें गोल करने के अधिक मौके बनाने की जरूरत थी और इस साल हमारा मुख्य ध्यान इसी पर रहेगा। यदि हम गोल करने के अधिक मौके बनाते हैं तो इससे हम निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे विशेषकर तब जबकि यह ओलंपिक वर्ष है। लालरेमसियामी ने कहा कि वह इस साल भारतीय टीम में अधिक प्रभाव छोडना चाहती हैं। उन्होंने कहा- मैं चार वर्षों से टीम में हूं और 2021 मेरे करियर में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि यह ओलंपिक वर्ष है। अभी तक मेरा करियर जैसे आगे बढ़ा है उससे मैं खुश हूं लेकिन मैं अब अधिक प्रभाव छोडना चाहती हूं। मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि आगामी महीनों में मैं भारतीय टीम में अधिक योगदान दे सकती हूं।

टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों पर बोले नीरज चोपड़ा- मुझे कुछ प्रतियोगिताओं में खेलने की जरूरत

मुंबई ।

ओलंपिक की तैयारियों में लगे भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा ने बुधवार को कहा कि अभ्यास के साथ साथ वह तोक्यो ओलंपिक से पहले कुछ प्रतियोगिताओं में खेलने को लेकर बेताब हैं क्योंकि चोट और कोविड-19 महामारी के कारण उनके पिछले दो साल 'बर्बाद' हुए। तोक्यो में पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे 23 वर्षीय नीरज ने कहा कि वह ओलंपिक से पहले कुछ प्रतियोगिताओं में खेलने को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साइ और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम (टॉप्स) द्वारा आयोजित वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में नीरज ने कहा- मैं अभ्यास में अपना शत प्रतिशत देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वैसा ही अभ्यास कर रहा हूं जैसे पहले किया करता था। अभ्यास अच्छा चल रहा है लेकिन मुझे प्रतियोगिताओं में खेलने की जरूरत है और हम इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा- मैंने टॉप्स और साइ से बात की और वे भी अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और यदि कुछ होता है तो मुझे प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि पिछले दो वर्षों से मैं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं खेल पाया हूं। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की सख्त जरूरत है। मेरा 2019 का साल चोट के कारण बर्बाद हुआ और अब 2020 और 2021 कोविड-19 के कारण बर्बाद चला गया। चोपड़ा ने बातचीत के दौरान प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया और कहा कि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभ्यास ही पर्याप्त नहीं होता है। उन्होंने कहा- यदि हम प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर अभ्यास का क्या फायदा। हम पिछले साल से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चाहिए। यदि हम ओलंपिक स्तर के बारे में सोचते हैं तो हमें उन एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी जरूरत होती है। चोपड़ा ने कहा- मुझे ओलंपिक में खेलने का अनुभव नहीं है। यह मेरे पहले ओलंपिक होंगे।

इटालियन ओपन : जोकोविच तीसरे दौर में पहुंचे

रोम।

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 7-6(5) से हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। जोकोविच मुकाबला जीतने के बावजूद अपना आपा खो बैठे और चेयर अंपायर से भिड़ गए। मैच में बारिश हो रही थी और अंपायर ने मैच को निलंबित नहीं किया था जिसको लेकर जोकोविच नाराज हो गए। जोकोविच ने अंपायर नाचो फोरकाडेल से कहा, आप कितनी देर तक मैच खेलवाना चाहते हैं। मैं आपसे तीन बार कह चुका हूं और आप कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं। मैच को दूसरे सेट में रोका गया जब स्कोर 5-5 था और तीन घंटे बाद जब खिलाड़ी वापस आए तब जोकोविच ने इस सेट को 7-6(5) से जीता। जोकोविच ने कहा, यह काफी अजीब मैच था जहां अजीब हालात थे। बारिश के कारण मैच रूकने की वजह से यह मेरे तथा फ्रिट्ज के लिए चुनौतीपूर्ण था।

फीफा ने कतर विश्व कप में श्रमिक कल्याण सुधार को लेकर बैठक की

लुसाने। विश्व फुटबाल की नियामक संस्था-फीफा ने 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले कतर में श्रमिकों के कल्याण सुधारों और व्यापक मानवाधिकारों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को कई सदस्य संघों और परिसंघों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। यह वर्चुअल बैठक कतर में सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लिगेसी (एससी) और फीफा के स्थानीय भागीदार के सहयोग से आयोजित किया गया था। बैठक में 2010 में जब कतर को 22वें फीफा विश्व कप के लिए चुना गया था तब से लेकर अब तक हुए देश के श्रम सुधार कार्यक्रम से संबंधित कई तथ्यों को स्पष्ट करने और चुनौतियों पर चर्चा की गई। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सदस्य संघों के साथ रचनात्मक जुड़ाव का बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी फीफा विश्व कप से जुड़े कार्यों में लगे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, और हमें विश्वास है कि यह आयोजन व्यापक सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है।

भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल में जडेजा और अश्विन दोनों को खेलाना चाहिए : ओझा

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा का कहना है कि टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों स्पिनरों को खेलाना चाहिए। ओझा ने कहा कि भारत के पास तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है, ऐसे में जडेजा टीम के बल्लेबाजी क्रम में एक विकल्प दे सकते हैं। ओझा ने स्पोर्टस टूडे से कहा, भारत को जडेजा और अश्विन दोनों को खेलाना चाहिए क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं। बड़ा प्वाइंट यह भी है कि जडेजा ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जडेजा के नाम घरेलू क्रिकेट में तीन तिहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जडेजा लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकते हैं और अश्विन ने भी हाल ही में शतक जड़ा था। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों स्पिनरों को खेलाना का थोड़ा भी मौका मिले तो इन्हें खेलाना चाहिए। किसी भी विकेट पर टीम को मैच जीताने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के पास बेहतर अनुभव है। ओझा ने कहा, ओवरऑल यह टीम शानदार है। मैं हनुमा विहारी को भी फोलो कर रहा हूं। उनका काउंटी क्रिकेट में खेलने का ख्याल अच्छा था।

सिंगापुर ओपन रद्द : साइना नेहवाल नहीं दिखेंगी टोक्यो ओलंपिक में

नई दिल्ली ।

बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने कोरोना वायरस से जुड़ी यात्रा पाबंदियों के कारण सिंगापुर में ओलंपिक की अंतिम क्वालीफाइंग को बुधवार को रद्द कर दिया जिससे भारत भारतीय खिलाड़ियों साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत की तोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। टूर्नामेंट का आयोजक सिंगापुर बैडमिंटन संघ (एसबीए) और बीडब्ल्यूएफ संयक्त रूप से सिंगापुर ओपन को रद्द करने को राजी हुए जिसका आयोजन एक से छह जून तक होना था। बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर पर सुपर 500 टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन ओलंपिक क्वालीफाइंग समय के दौरान 'रेस टू तोक्यो' रैंकिंग के लिए रैंकिंग अंक देने वाला आखिरी टूर्नामेंट था। बीडब्ल्यूएफ ने बयान में कहा- सभी खिलाड़ियों, टूर्नामेंट कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हितों को देखते हुए टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। बीडब्ल्यूएफ पुष्टि करता है कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। बयान के अनुसार- आयोजकों और बीडब्ल्यूएफ ने सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए सभी प्रयास किए। हालांकि दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण यहां आने वाले यात्रियों को लेकर जटिल चुनौतियां थी। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि वह तोक्यो ओलंपिक क्वालीफाइंग को लेकर बात में बयान जारी करेगा। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना और श्रीकांत का ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना सिंगापुर ओपन के नतीजे पर निर्भर करता था क्योंकि इससे पहले सात मई को मलेशिया ओपन (25 से 30 मई) को भी स्थगित कर दिया गया था। मलेशिया ओपन के स्थगित होने के बाद भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने बीडब्ल्यूएफ ने अपने खिलाड़ियों के क्वालीफिकेशन को लेकर स्पष्टता की मांग की थी। सिंगापुर ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है जिससे भारतीय खिलाड़ियों का अंतिम क्वालीफायर के लिए इस देश में जा पाना काफी मुश्किल था। भारत के लिए महिला एकल में पीवी सिंधू, पुरुष एकल में बी साई प्रणीत और चिराग शेट्टी तथा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

शतरंज की ऑनलाइन गेम साइट ने कोरोना राहत के लिए जुटाए पांच हजार डॉलर

चेन्नई। ऑनलाइन शतरंज गेम साइट चेस डॉट कॉम ने कोरोना राहत के लिए अबतक पांच हजार डॉलर का फंड जुटा लिया है। वेबसाइट ने उन लोगों द्वारा यह फंड जुटाया है जो पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद, कोनेरु हम्पी, द्रोनावली हरिका, निहाल सरिन और आर. प्रगनानंधा के खिलाफ 13 मई को मुकाबला खेलेंगे। यह सभी पांचों ग्रैंडमास्टर ऑनलाइन गेम में हिस्सा लेंगे। चेस डॉट कॉम के अनुसार, मैच की डोनेशन राशि 10000 डॉलर तक जाएगी। सभी फंड रेड क्रॉस इंडिया और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के चेकमेट कोविड फंड में जाएगा। फंड का 70 फीसदी हिस्सा रेड क्रॉस इंडिया और 30 फीसदी एआईसीएफ के पास जाएगा। चेस डॉट कॉम के अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि 100 स्लॉट हैं जिसमें से 20 आनंद के साथ खेलेंगे जिसके लिए 150 डॉलर लगेंगे। अभी तक जितने स्लॉट बुक हुए हैं उसमें से 3000 डॉलर आ चुके हैं। अन्य चार ग्रैंडमास्टर के साथ खेलने के लिए 25 डॉलर लगेंगे जिससे अबतक 2000 डॉलर आए हैं। अधिकारी ने कहा, जब हम शो शुरू करेंगे तो हमारा लक्ष्य 15000 डॉलर एकत्र करना था। बाकी दर्शकों के देखने पर निर्भर करता है। हाल ही में एआईसीएफ के सचिव ने आईएएनएस को बताया था कि चेकमेट कोविड पहल से अबतक 60 लाख रूपये जुटाए गए हैं।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीताजी ने ट्रोल होने के बाद मांगी माफी

यदि किसी शब्द का आप मतलब नहीं जानते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर ये गलती लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बबीताजी का किरदार अदा करने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता कर गईं। जब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की आवाज उठने लगी तो अब माफी मांग रही हैं। हुआ यूं कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लि?पस्टिक के रंग के बारे में वे बात कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने पिछड़ी जाति के खिलाफ गलत शब्द बोल दिया कि मैं .... इसकी तरह नहीं दिखना चाहती। मुनमुन ने यह बोला और वीडियो वायरल हो गया। एससी-एसटी के नेताओं ने मुनमुन को गिरफ्तार करने की मांग की है। मुनमुन का कहना है ?कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वे तो इस शब्द का मतलब भी नहीं जानती। माफी मांग रही हैं, लेकिन लोग मुनमुन को लगातार लताड़ लगा रहे हैं।

दिव्या खोसला ने लगवाई कोरोना वैसीन की पहली डोज

कोरोनावायरस ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। इस महामारी से लड़ने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम तेज हो गया है। कई सेलेब्स भी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे है। हाल ही में एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। दिव्या खोसला कुमार ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन लगवाते हुए एक वीडियो शेयर कर फैंस को इस बात कि जानकारी दी है। वीडियो को शेयर करने के साथ ही दिव्या ने अपने फैंस से भी कोविड वैक्सीन लेने की अपील भी की है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के बाद दिव्या को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, वैक्सीन लगवाते हुए दिव्या ने अपना मास्क नीचे कर लिया था। जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कई यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते हुए एक्ट्रेस को मास्क पहनने की सलाह दी है। दिव्या खोसला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, टीकाकरण पूरा, आज मैंने अपना पहला टीका ले लिया है, मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप भी अपना नामांकन करें, और वैक्सीन लगवा लें! हम सब इसमें एक साथ हैं, चलो टीकाकरण और दिशानिर्देशों का पालन करके वायरस को हराएं।

सफेद नागिन के अवतार में मौनी रॉय ने शेयर की तस्वीर

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे भारत में त्रासदी मचा रहा है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने लॉकडाउन लाया हुआ है। ऐसे में लोग अपने घरों में है। ऐसे में बॉलीवुड सितारें भी घर पर हैं और अपने फैंस का घर से ही मनोरंजन कर रहे हैं। टीवी की नागिन मौनी रॉय को अपने पुराने दिनों की याद आ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें शेयर की है। मौनी रॉय ने मंगलवार (11 मई) को अपने इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर कई थ्रोबैक तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरें ऐसे समय में कैप्चर की गईं जब हालात ऐसे नहीं थे। इन फोटोज में मौनी काफी खुश नजर आ रही हैं और लगता है कि वह अपने दिन का आनंद ले रही हैं। मौनी रॉय ने कई तस्वीरें साझा कीं, जहां वह लंबी सफेद ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। प्रतीत होता है कि तस्वीरें एक रेस्तरां में क्लिक की गई थीं मौनी ने तस्वीरों को कैप्शन दिया थ्रोबैक टू हैप्पी टाइम।

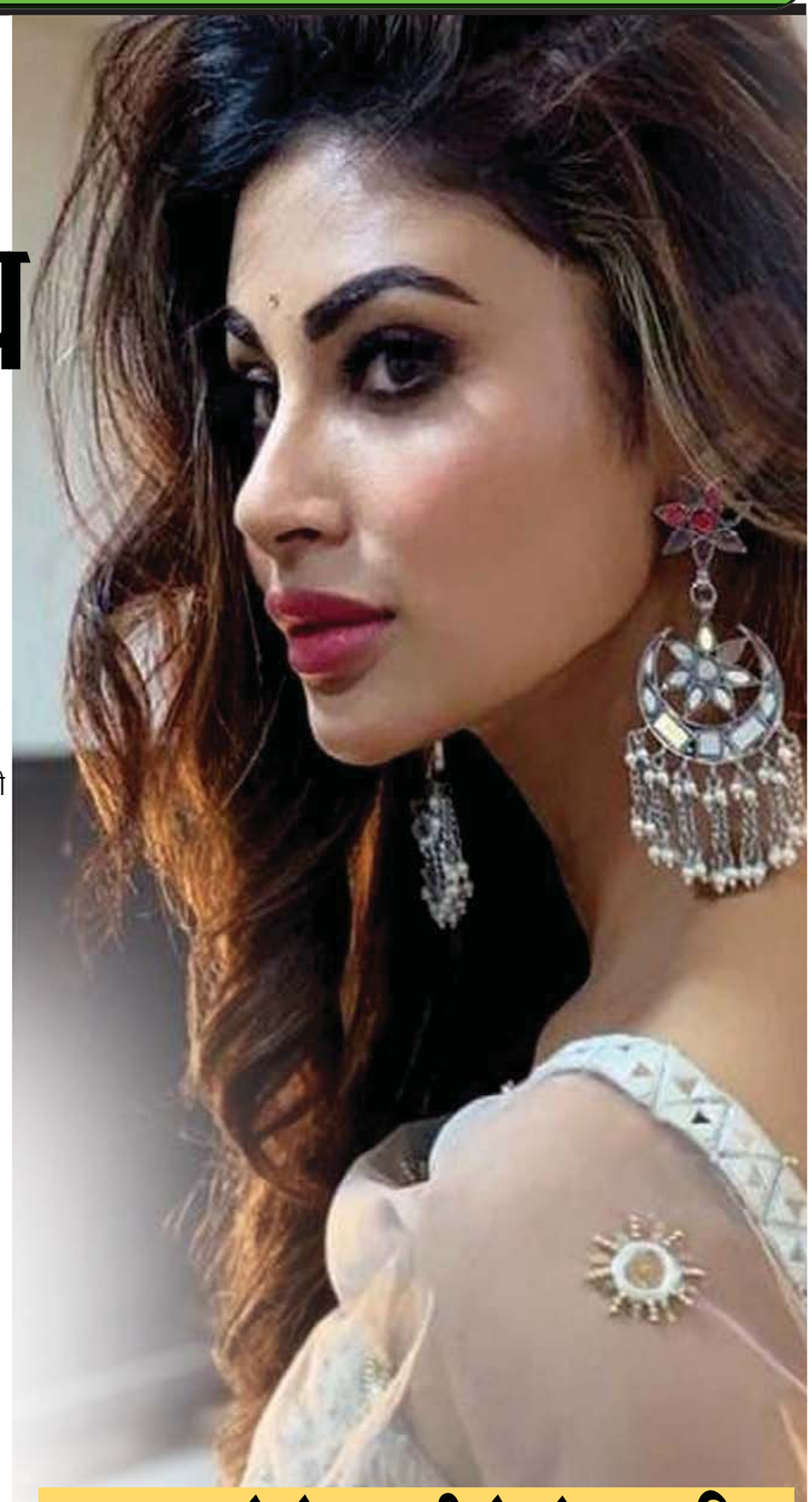

ईद पर आएगी फिल्म राधे? सलमान खान मे किया अपने फैंस से यह वादा

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपने प्रशंसकों से किया वादा पूरा करते हुए देश के कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में होने के बावजूद अपनी फिल्म 'राधे - यॉर मॉस्टवॉन्टेड भाई' को ईद पर रिलीज करने का फैसला किया है। सलमान ने 'जूम राउंडटेबल' साक्षात्कार में सोमवार रात कहा कि जिन लोगों ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' देखी है, वे उनसे प्यार करते हैं और अब उनके बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं। मुंबई से उन्होंने कहा, '' मैं काफी खुशकिस्मत तथा कृतज्ञ हूं कि मेरे प्रशंसक बेहद वफादार हैं। दादा-दादी से माता-पिता... माता-पिता से नाती-पोते हर आयुवर्ग में मेरे प्रशंसक हैं।'' अभिनेता की फिल्म 13 मई को ओटीटी मंच 'डीटीएच' पर प्रसारित की जाएगी। फिल्म में सलमान मुंबई में मादक पदार्थों के गिरोह से निपटने वाले एक एनकाउंटर विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के सलमान की 2009 में आई फिल्म 'वॉन्टेड' का सीक्वल होने की अटकलों पर सलमान ने स्पष्ट किया कि यह एक नई कहानी और केवल किरदार का नाम एक है तथा वह भी अपने किए वादे पूरे करता है। साथ ही सलमान ने वक्त के साथ-साथ एक्शन के और चुनौतीपूर्ण होने की बात भी कही। उन्होंने कहा, '' मुझे पता नहीं कि एक्शन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है या मेरे लिए यह चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन मैं अब भी इसे कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप जब तक एक्शन कर सकते हैं तब तक आप रोमांस कर सकते हैं। लोगों को एक्शन और रोमांस देखना पसंद है और मैं वहीं करने की कोशिश कर रहा हूं।'' फिल्म में सलमान के अलावा दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ और गौतम गुलाटी भी नजर आएंगे।

अनन्या पांडे ने इंडस्ट्री में दो साल किए

अनन्या पांडे ने इंडस्ट्री में 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन दो वर्षों में अभिनेत्री को आगे बढ़ते हुए और एक परफ़ॉर्मर के रूप में बदलते हुए देखा है। अनन्या ने शो-बिज में पैर जमाने के बाद से हर बार खुद को साबित किया है। अपने सफर को दर्शाते हुए, अभिनेत्री ने साझा किया, पिछले दो वर्षों में यह एक शानदार सफर रहा है और मैं वास्तव में बहुत आभारी और धन्य हूं जो अपने सपने को जी रही हूं। अपने आस-पास के सभी लोगों के प्यार, प्रोत्साहन, ज्ञान और सलाह के बिना यहां होना संभव नहीं था। मैं उन सभी तकनीशियन, निर्देशकों, डीओपी और अभिनेताओं की हमेशा आभारी हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने उनमें से हर एक से बहुत कुछ सीखा है, जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। उन्होंने कहा, मेरे प्रशंसकों के बिना कुछ भी संभव नहीं था (मुझे यह शब्द को पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अननियन्स नाम से संबोधित करूंगी- एक ऐसा शब्द जो उन्होंने खुद के लिए तैयार किया है) जो असीम प्यार वे मुझे हर दिन बरसाते हैं वह मुझे दोगुना काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी कड़ी मेहनत करती रहूंगी, अपने आप को चुनौती देती रहूंगी, कभी भी सीखना बंद नहीं करूंगी और फिल्म के सेट पर और भी बहुत सारे एडवेंचर के लिए तैयार हूं। अनन्या ने आगे कहा, यह बहुत कठिन समय है, ऐसे में सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए ये आशा और प्रार्थना करती हूं और मैं सभी के लिए प्यार और प्रार्थना भेज रही हूं। उम्मीद है कि फिल्मों का जादू बहुत जल्द वापस आएगा।

सदाशिव अमरापुरकरः आखिरी रास्ता देखने के बाद दर्शक उनसे नफरत करने लगे थे

सदाशिव अमरापुरकर को ज्यादातर हिंदी फिल्मों में खलनायकी करते देखा गया है। विलेन के रोल को निभाने के लिए उनके पास न हृष्ट-पुष्ट शरीर था और न ही दमदार आवाज, बावजूद इसके उन्होंने विश्वसनीयता के साथ खलनायकी के रंग दिखाए। पतली आवाज को संवाद अदायगी के जरिये बखूबी पेश करना और चेहरे पर ऐसे भाव लाना कि दर्शक उनसे नफरत करने लगे, सदा?शिव के अभिनय की खासियत थी। धर्मेन्द्र की एक फिल्म में सदाशिव ने भी अभिनय किया था। धर्मेन्द्र जब फिल्म डब कर रहे थे तो सदाशिव का अभिनय भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म जरूर चलेगी क्योंकि सदाशिव की खलनायकी देख उन्हें ही गुस्सा आ रहा है तो दर्शक तो बैचेन हो जाएंगे। भेड़चाल के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड ने उन्हें ज्यादातर खलनायक की भूमिका ही निभाने को दी, लेकिन सदाशिव को सिर्फ 'खलनायक' की भूमिका में बांधना उनके प्रतिभा के साथ न्याय करना नहीं होगा। मराठी नाटकों और फिल्मों में उन्होंने कई तरह के चरित्र निभाए। 11 मई 1950 को जन्मे सदाशिव अमरापुकर का वास्तविक नाम गणेशकुमार नरवाड़े था। पहले उनका रुझान गायकी की ओर था, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनय में करियर बनाने का निश्चय किया। 1974 में जब वे नाटक करने लगे तो अपना नाम बदल लिया। मराठी नाटक 'आमरस' से वे चर्चा में आए और मराठी फिल्मों में व्यस्त हो गए। 1982 में वे 'हैंड्स अप' नामक नाटक कर रहे थे और दर्शकों में गोविंद निहलानी बैठे हुए थे। गोविंद उस समय अपनी फिल्म 'अर्धसत्य' के लिए कलाकार चुन रहे थे। सदाशिव का अभिनय उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने 'अर्द्धसत्य' में सदाशिव को अहम रोल सौंप दिया। इस फिल्म में रामा शेट्टी के रूप में सदाशिव का अभिनय देख दर्शक दंग रह गए और सदाशिव रातों-रात प्रसिद्ध हो गए। ओम पुरी जैसे विश्वस्तरीय अभिनेता के सामने सदाशिव अपने अभिनय की छाप छोड़ने में सफल रहे। अर्द्धसत्य के बाद हिंदी फिल्मों ने सदाशिव को हाथों-हाथ लिया और सदाशिव ने ढेर सारी फिल्में साइन की। उन्होंने हास्य तथा चरित्र भूमिकाएं भी निभाईं। इनमें से कई फिल्मों में वे महत्वहीन रोल में भी नजर आएं। सदाशिव ने खलनायक के रूप में कई यादगार भूमिकाएं की और उस दौर के सुपरस्टार्स से टक्कर लेते नजर आए। 'हुकूमत' (1987) में उन्होंने धर्मेन्द्र से टक्कर ली। 1986 में प्रदर्शित फिल्म आखिरी रास्ता में उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए मुश्किलें पैदा की। आखिरी रास्ता देखने के बाद कई दर्शक उनसे नफरत करने लगे थे। खतरों के खिलाड़ी (1988), सच्चे का बोलबाला (1989), ईश्वर (1989), एलान-ए-जंग (1989), वीरू दादा (1990), फरिश्ते (1991), इज्जत (1991) जैसी सफल फिल्मों का वे हिस्सा बने। 1991 में आई प्रदर्शित 'सड़क' में सदाशिव अमरापुरकर के करियर की श्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। उन्होंने एक किन्नर का रोल निभाया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इस रोल के लिए उन्हें फिल्मफेअर पुरस्कार भी मिला। सन् 2000 तक सदाशिव फिल्मों में काफी व्यस्त रहे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी, बंगाली और उड़िया फिल्मों में अभिनय के रंग बिखेरे। बाद में उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली और दो वर्ष तक अमेरिका में रहे। इस दौरान उन्होंने काम नहीं किया। टीवी धारावाहिक 'शोभा सोमनाथ की' के जरिये उन्होंने अभिनय की दुनिया में वापसी की। श्याम बेनेगल के धारावाहिक 'राज से स्वराज' तक में उन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया। बेनेगल के धारावाहिक 'भारत एक खोज' में उन्होंने ज्योतिबा फुले का रोल निभाया। बड़े परदे पर अंतिम बार वे 'बॉम्बे टॉकीज' (2013) में दिबाकर बैनर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म में दिखाई दिए। यह रोल उन्होंने अपनी बेटी के कहने पर किया था। फेफड़ों के इंफेक्शन के कारण कुछ समय वे अस्पताल में भर्ती रहे और 3 नवंबर 2014 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नई टिहरी वर्तमान का शहर

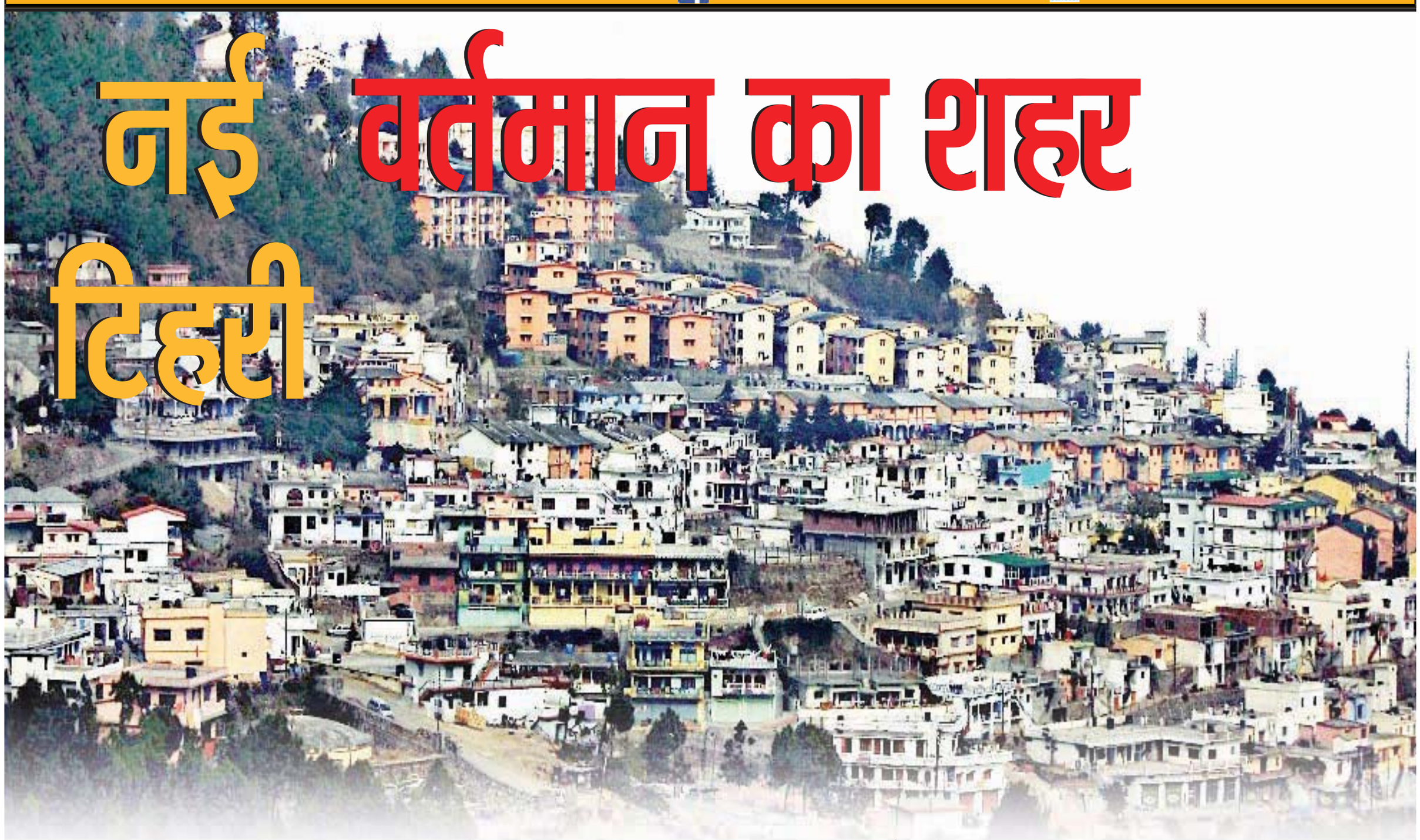

टिहरी गढ़वाल भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला है। इसके अतिरिक्त टिहरी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। पर्वतों के बीच स्थित यह जगह काफी खूबसूरत है। हर वर्ष काफी संख्या में पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं। यह स्थान धार्मिक स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। यहां आप चम्बा, बुदा केदार मंदिर, कैम्पटी फॉल, देवप्रयाग आदि स्थानों में घूम सकते हैं। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खिंचती है। कुछ सालों पहले ही बनी नई टिहरी धीरे-धीरे पर्यटकों को अपनी ओर लुभाने में कामयाब तो हो रही है लेकिन पुराने पर्यटकों के दिमाग में आज भी पुरानी टेहरी ही इससे ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि जब नई टिहरी को बसाने का काम शुरु किया गया तब सरकार द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि नई टिहरी में भी पुरानी झलक यहां आने वाले पर्यटकों को दिखे।

उत्तराखंड में स्थित यह शहर 21वीं सदी का हिल स्टेशन कहा जा सकता है। सागरतल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसा शहर भागीरथी नदी पर बने टिहरी डैम के निकट पहाड़ियों पर बसा है। इस आधुनिक शहर का इतिहास बस इतना है कि देश के विकास के लिए बने विशाल बांध के जलाशय में जलमग्न होने वाले प्राचीन टिहरी शहर के विस्थापितों के लिए नई टिहरी शहर बसाया गया था। इस शहर को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसलिए यहां के घर, फ्लैट, कार्यालय और बाजार समरूपता लिए हुए हैं। यही इस पर्वतीय शहर की विशेषता है।

प्रकृति की खूबसूरती से भरपूर नई टिहरी स्वास्थ्यवर्द्धक आबोहवा का धनी है। इस शहर का कोई अतीत नहीं है। यहां केवल वर्तमान है। जो नए आलीशान मंदिर, गुरुद्वारे, मसजिद और चर्च के रूप में नजर आता है। शहर के बीच से गुजरता मुख्य मार्ग यहां का मॉल रोड कहलाने लगा है, जिसके आसपास साफ सुथरा बाजार है। यहीं कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। सैलानी इसी मार्ग पर चहलकदमी करते हुए दूर तक निकल जाते हैं। दुकानों आदि का क्रम खत्म होने के बाद इस पर घने पेडों का सिलसिला शुरू हो जाता हैए जहां शीतल हवाओं से भरा वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। मॉल रोड पर एक शहीद स्मारक है। एक बड़े पत्थर पर उन शहीदों के नाम अंकित हैं, जिनकी स्मृति में यह स्मारक बना है।

नई टिहरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक मनोरम स्थान है। यहां से पर्यटकों को हिमाच्छादित पर्वतों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसलिए लोगों ने इस स्थान को स्नो व्यू का नाम दे दिया। यह स्थान एक पिकनिक स्पॉट के समान है। एकाकीपन की तलाश में आए सैलानी यहां घंटों बैठ कर प्राकृतिक दृश्य निहारते रहते हैं। इस स्थान से कुछ दूर देव दर्शन नामक स्थान है। यहां एक मंदिर है। नई टिहरी के सभी मंदिर नए हैं, लेकिन इनमें स्थापित प्रतिमाएं पुराने टिहरी शहर के मंदिरों से लाकर यहां प्रतिष्ठित की गई हैं। इस स्थान से टिहरी बांध की विस्तृत झील का मोहक दृश्य देखते ही बनता है।

नए शहर का दूसरा हिस्सा बौराडी है। यह कुछ नीचे की पहाड़ी पर बसा है। यहां कुछ मंदिर हैं और एक भव्य गुरुद्वारा है। पुराने टिहरी शहर की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए यहां एक क्लॉक टॉवर बनाया गया है। इसके निकट ही यहां का स्टेडियम स्थित है। घुमावदार सडकों के अलावा नई टिहरी में नीचे से ऊपर की ओर कई सीढीनुमा मार्ग भी हैं। इसलिए इसे सीढ़ियों का शहर कहना गलत न होगा। भागीरथी पुरम के पास टॉप टैरेस नामक स्थान भी सैलानियों को आकर्षित करता है। यहां से भी विस्तृत झील का दृश्य बड़ा मनोहारी प्रतीत होता है। नई टिहरी से 11 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का प्राचीन शहर चंबा स्थित है। नई टिहरी अब धीरे-धीरे सप्ताहांत की शानदार सैरगाह बनता जा रहा है।

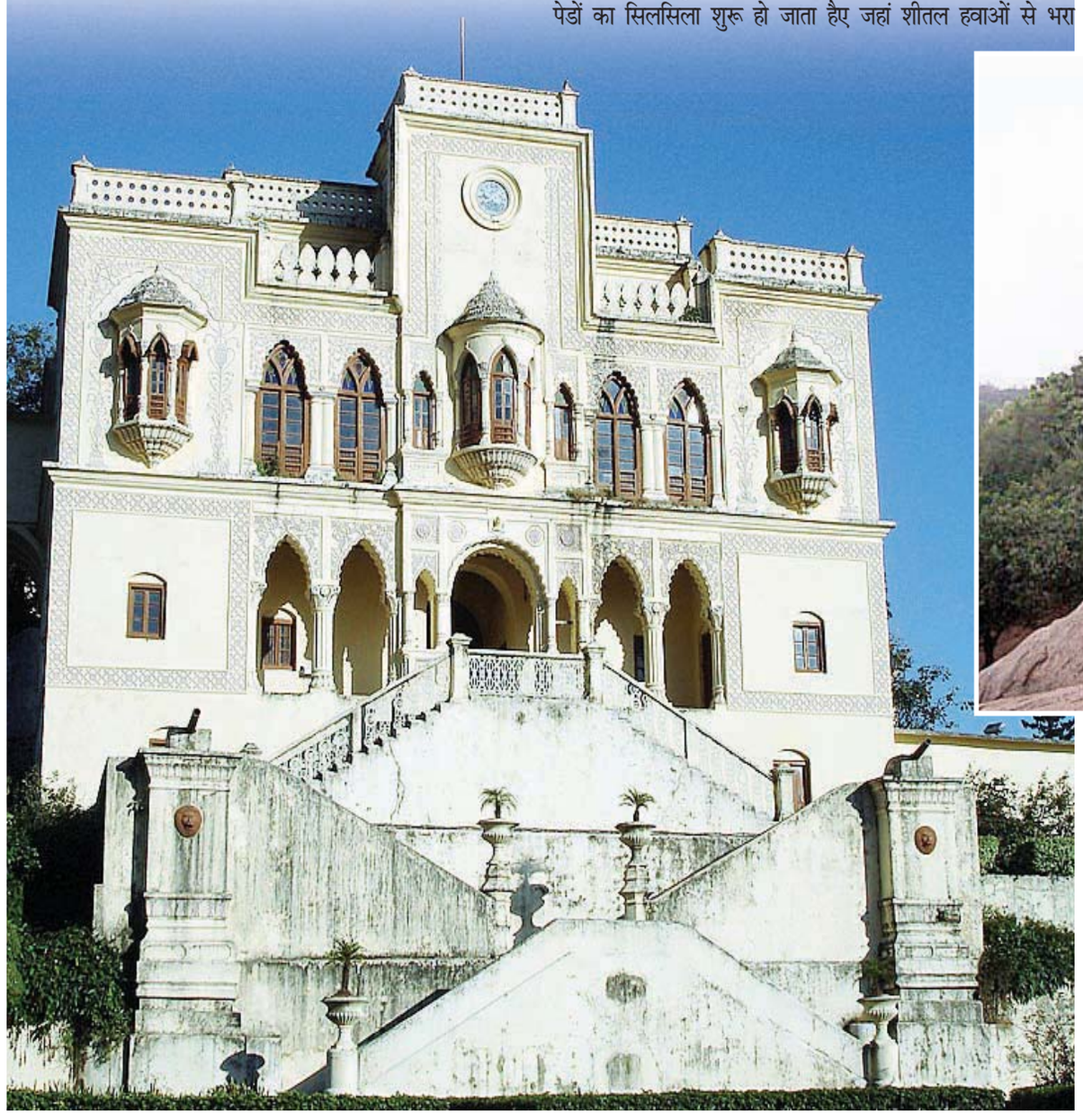

कोलाहल से दूर कुदरती सौंदर्य का शहर रानीखेत

रानीखेत को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य रानीखेत के कण-कण में बिखरा पड़ा है। यहां पर दूर-दूर तक फैली घाटियां, घने जंगल तथा फूलों से ढंके रास्ते व ठंडी मस्त हवा पर्यटकों का मन बरबस ही मोह लेती है। रानीखेत की खास बात यह है कि यहां पर लोगों का कोलाहल व भीड़भाड़ बहुत कम है। यकीन जानिए यहां पहुंचने के बाद पर्यटक स्वयं को प्रकृति के निकट पाता है।

अंग्रेजों के शासन के दौरान अंग्रेजी फौज की छावनी रहे इस क्षेत्र में कुमांऊ रेजीमेंट का मुख्यालय भी है। छावनी क्षेत्र होने के कारण एक तो यहां वैसे ही साफ-सफाई रहती है दूसरे यहां पर प्रदूषण की मात्रा भी अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत कम है। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चौबटिया। चौबटिया में बहुत ही सुंदर बागबगीचे हैं। यहां पर स्थित सरकारी उद्यान व फल अनुसंधान केंद्र भी देखने योग्य हैं। यहां पर पास में ही एक जल प्रपात है, जिसके ऊंचाई से गिरते संगमरमर जैसे पानी का दृश्य आपका मन मोह लेगा।

द्वाराहाट रानीखेत से लगभग 32 किमी की दूरी पर स्थित है। द्वाराहाट पुरातात्विक दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कभी कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी रहे इस स्थल पर पूरे 65 मंदिर हैं जोकि तत्कालीन कला के बेजोड़ नमूने के रूप में विख्यात हैं। बदरीकेदार मंदिर, गूजरदेव का कलात्मक मंदिर, पाषाण मंदिर और बावड़ियां पर्यटकों को अपने अतीत की गाथा सुनाते हुए लगते हैं। यहां स्थित मंदिरों में से विमांडेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर एवं कुबेर की विशालकाय मूर्ति देखना न भूलें।

रानीखेत से 6 किमी की दूरी पर स्थित है उपत एवं कालिका। यहां पर गोल्फका विशाल मैदान है। हरी-हरी घास से भरे इस मैदान में गोल्फ खेलने का आनंद ही कुछ और है। कालिका में कालीदेवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। अब आप दूनागिरी जा सकते हैं। द्वाराहाट से लगभग 14 किमी की दूरी पर स्थित दूनागिरी से आप हिमालय की बर्फ से ढंकी चोटियों के मनोहारी दर्शन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर 1181 के शिलालेख भी पाए गए हैं। दूनागिरी में चोटी पर दुर्गा जी सहित अन्य कई मंदिर भी हैं जहां पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इस स्थान को पर्यटन के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ भी कहा जा सकता है।

शीतलाखेत को आप पर्यटक गांव भी कह सकते हैं। यहां तक आने के लिए आप रानीखेत व अल्मोड़ा से सीधी बस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। ऊंचाई पर शांत व खूबसूरत नजारों से भरे दृश्य पर्यटकों को भा जाते हैं। ट्रैकिंग की दृष्टि से भी यह अच्छा स्थल है। आप चिलियानौला भी घूमने जा सकते हैं। यहां पर हेड़ाखान बाबा का भव्य मंदिर है। कहते हैं कि इस आधुनिक मंदिर में देवी-देवताओं की कलात्मक मूर्तियां देखने लायक हैं। द्योलीखेत का मैदान तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके एक ओर देवदार तथा चीड़ के वृक्ष इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं।

खड़ी बाजार रानीखेत का मुख्य बाजार है। एक ओर से उठे होने के कारण ही शायद इसका नाम खड़ी बाजार पड़ा। इस बाजार के दोनों ओर दुकानें हैं जहां से आप रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले सामानों के साथ ही स्थानीय काष्ठकला की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों के लिए रानीखेत के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ट्रैकिंग करके आप अपनी यात्रा को रोमांचक बनाने के साथ ही यादगार भी बना सकते हैं।

आसपास के दर्शनीय स्थानों की सैर पर जाने के लिए आपको यहां से निर्धारित दरों पर टैक्सी मिल सकती हैं। यदि आप भारवाहकों की सेवा लेने चाहें तो दाम पहले ही तय कर लें। बस सेवा कुछ ठीकठाक नहीं कही जा सकती। अप्रैल व जून तथा सितंबर से नवंबर के बीच आप जब भी चाहें, रानीखेत घूमने जा सकते हैं क्योंकि यह माह यहां की सैर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। रानीखेत आप जब भी जाएं, ऊनी कपड़े साथ रखना नहीं भूलें।

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

कनाडा में रिश्तेदार ने भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या की, शव को भारत लाने की तैयारी

टोरंटो। कनाडा में 43 वर्षीय व्यक्ति को अपने 19 वर्षीय रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या और अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने का आरोपित किया गया है। एडमनटन में गुमदुर सिंह बरार ने अपने रिश्तेदार हरमनजोत सिंह भट्टल की हत्या कर दी और अपनी पत्नी सतवीर कौर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे फर्स्ट डिग्री हत्या और हत्या के प्रयास का आरोपित बनाया गया है। पंजाब के बरनाला जिले के भट्टल गांव से हरमनजोत सिंह भट्टल शिक्षा वीजा पर दिसंबर 2018 में कनाडा आया था। वह अपने माता-पिता की एक मात्र संतान था। वह उत्तरी अल्बर्टा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में पढ़ रहा था और मां के रिश्तेदार के यहां ठहरा हुआ था। आरोपित का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने उस वाहन पर गोली चला दी जिसमें उसकी पत्नी भट्टल के साथ यात्रा कर रही थी। भट्टल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि सतवीर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। भट्टल और सतवीर को गोली मारने के बाद गमदुर घटनास्थल से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भट्टल के शव को भारत भेजे जाने के लिए अभियान शुरू किया गया है।

भारत ने अब से पहले इतनी भयावह आपदा नहीं देखी, विश्व भर में बसे भारतीय करें मदद: रंगस्वामी

वाशिंगटन। एक प्रख्यात भारतीय-अमेरिकी समाजसेवी और सिलिकान वैली के पूंजीपति ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय से अपील की है कि वह इस संकटकाल में भारतीयों की पूरी मदद करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का मौजूदा संकट बेहद खतरनाक है और भारत ने अब तक इतनी भयावह आपदा का पहले कभी सामना नहीं किया है। कोविड-19 के चलते चेन्नई में अपनी बहन को खो चुके अमेरिका में भारतीय समुदाय के संस्थापक एमआर रंगस्वामी ने बुधवार को कहा कि भारत ने अब तक इससे बड़ा संकट नहीं देखा। इसलिए मैं अमेरिकी-भारतीय समुदाय के लोगों से अपील करता हूं कि वह भारत में अपने परिवार और मित्रों की मदद करें। लेकिन इस पर ही नहीं रुकें और यह ऐसा समय है कि सभी को अधिकाधिक मदद करनी चाहिए। सिलिकान वैली में केंद्रित रंगस्वामी ने कहा कि अमेरिका और विश्व के अन्य स्थानों में बसे भारतीयों को भारत के लोगों के लिए अधिकाधिक संसाधन और धन जुटाने की जरूरत है। भारतीय लोग आजादी के बाद जनस्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसा संकट रोज-रोज नहीं आता। इसलिए यह ऐसा समय है जब हमें अपनी भरपूर साम?र्थ्य से दान करना चाहिए, अपनी सोच से परे जाकर उपाय खोजने चाहिए और हम जो करना चाहते हैं उससे बढ़चढ़ कर प्रयास करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि 15 लाख डालर की मदद 'हेल्प तमिलनाडु ब्रीद' अभियान के तहत की गई है।

अमेरिका ने कोरोना संकट में निभाया साथ, भारत को अब तक कुल 50 करोड़ डालर की सहायता सामग्री भेजी

वाशिंगटन। अमेरिका कोविड-19 वैश्विक महामारी की अप्रत्याशित दूसरी लहर के दौरान लगातार पैदा हो रही जरूरतों को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अमेरिकी सरकार ने अब तक 10 करोड़ डालर (करीब 7,34,29,50,000 रुपये) मूल्य की सहायता सामग्री दी है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र ने भी 40 करोड़ डालर (करीब 29,36,16,00,000 रुपये) मूल्य की अतिरिक्त सहायता सामग्री दान की है। यानी भारत को कुल 50 करोड़ डालर (करीब 36,69,70,00,000 रुपये) की सहायता सामग्री भेजी गई है।

अमेरिकी संसद में हिंसा पर पूर्व रक्षामंत्री ने दी गवाही, कहा- सेना जल्द भेजने से हो सकता था तख्तापलट का भ्रम

वाशिंगटन, एपी। अमेरिका में चुनावों के बाद संसद (कैपिटल हिल) में हिंसा की घटना में प्रशासनिक स्तर पर लिए गए सभी निर्णयों की जिम्मेदारी तत्कालीन कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर ने अपने ऊपर ली है। उन्होंने देरी से सेना के पहुंचने पर सफाई दी है कि पहले से सेना भेजने पर समर्थकों में तख्तापलट का भ्रम हो सकता था। ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता। इस संबंध में संसद की ओवर साइट कमेटी के सामने पेश होकर अपने सभी निर्णयों के बारे में तत्कालीन कार्यवाहक रक्षा मंत्री मिलर ने दलील दी। संसद की कमेटी को दिए पूर्व लिखित बयान में मिलर ने कहा है कि वे यह मानते हैं कि सेना का किसी भी कार्रवाई में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह एकदम सेना का इस्तेमाल प्रशासनिक स्तर पर उचित नहीं मानते हैं। पूर्व में हुई घटनाओं के कारण वह उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते थे। मिलर ने इस बात से भी इनकार किया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घटना के समय रक्षा मंत्रालय में कोई दखल था। सुनवाई करने वाली कमेटी की अध्यक्ष कैरोलिन मैलोनी ने कहा कि हमारी सुनवाई में पहली बार अमेरिकी जनता को ट्रंप कार्यकाल के शीर्ष अधिकारियों से यह जानकारी मिल सकेगी कि संसद पर हमले में इतनी लापरवाही क्यों और किस कारण हुई।

नेपाल कांग्रेस अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, संख्या बल जुटाने की कोशिश

लंदन। (एजेंसी)।

काठमांडू। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (एनसी) ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश करने का फैसला किया है। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ने राजनीतिक पार्टियों से बृहस्पतिवार तक नई सरकार गठन करने को कहा था क्योंकि के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली हुकूमत विश्वास मत हार चुकी है। एनसी के पदाधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में अगली सरकार बनाने पर फैसला किया गया है। शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली पार्टी को नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) का समर्थन हासिल है और उसे उम्मीद है कि जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (जेएसपीएन) के सांसद भी उसकी हिमायत करेंगे।

राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के दफ्तर ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। 'द हिमालयन टाइम्स' की खबर के मुताबिक, इसने सीपीएन-यूएमएल के माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल के नेतृत्व वाले धड़े के सांसदों को सरकार गठन में मदद करने के लिए प्रभावित करने की उम्मीद भी जताई है। खबर के मुताबिक, 271 सदस्यीय प्रतिनिधिसभा में एनसी के पास 61 सदस्य हैं जबकि सीपीएन-एमसी के 49 सांसद हैं। पार्टी को अपने नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए 26 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी।

जेएसपी-एन के 32 सदस्य सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जेएसपी-एन के महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो की अगुवाई वाले धड़े के 15 सांसद सोमवार को हुए विश्वास मत के दौरान तटस्थ रहे थे और उन्होंने अभी इस बात का फैसला नहीं किया है कि वे एनसी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगे या नहीं। एनसी के संयुक्त सचिव प्रकाश शरण महत ने मंगलवार को बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ÷जेएसपी-एन मुद्दे पर बंटी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जेएसपी-एन बृहस्पतिवार की समय सीमा तक सरकार गठन में हमें समर्थन देगी।÷

उन्होंने कहा कि सीपीएन-एमसी की अगुवाई करने वाले पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने पार्टी को आश्वास्त किया है कि एनसी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए वह समर्थन देंगे। अगर जेएसपी-एन एनसी का समर्थन नहीं करती है तो पार्टी यूएमएल के नेपाल-खनाल गुट के 28 सांसदों को इस्तीफा देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इस स्थिति में सदन की क्षमता घटकर 243 रह जाएगी और एनसी तथा सीपीएन-एमसी, उपेंद्र यादव और बाबूराम भट्टाराय के प्रति निष्ठा रखने वाले जेएसपी-एन के 15 सांसदों के साथ मिलकर सरकार बना सकेंगी। अनुच्छेद 76 (2) के तहत अगर सदन में किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति सदन के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती हैं जो प्रतिनिधि सभा की दो या अधिक पार्टियों से बहुमत जुटा सकता है।

'काठमांडू पोस्ट' ने खबर दी है, अगर सदन अनुच्छेद 76 (2) के तहत सरकार बनाने में नाकाम रहता है या इस प्रावधान के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री 30 दिन के अंदर विश्वास्त मत हासिल करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 (3) लागू कर सकती हैं। उस स्थिति में ओली एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। ओली सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। अगर ओली को संविधान के तहत नियुक्त किया जाता है तो उन्हें नियुक्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर विश्वास मत जीतना होगा। नेपाल में पिछले साल 20 दिसंबर को तब राजनीतिक संकट गहरा गया था जब प्रधामंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने और चुनाव कराने की घोषणा की थी। ओली ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में सत्ता टकराव के बीच यह सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत ने फरवरी में सदन को भंग करने के फैसले को खारिज करते हुए उसे बहाल कर दिया था।

इजराइल और हमास के बीच तेज हुए रॉकेट हमले, पीएम नेतन्याहू ने कहा लंबा चल सकता है संघर्ष

यरुशलम। (एजेंसी)।

इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए। उसने दो बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उनके ठिकानों में कम से कम तीन चरमपंथियों को मार गिराया। वहीं, फलस्तीन की ओर से इजराइल में भी लगातार रॉकेट हमले हुए। दोनों शत्रुओं के बीच 2014 के बाद से यह सबसे बड़ी लड़ाई है और इसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले तेज करने का आह्वान किया जबकि गाजा के चरमपंथियों ने देर रात तक रॉकेट दागे जिससे घनी आबादी वाले तेल अवीव इलाके में विस्फोटों की आवाज सुनाई देती रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रॉकेट हमले में इजराइल में तीन महिलाओं की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

गाजा में 10 बच्चों समेत 32 फलस्तीनियों की मौत हो गई। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच यह लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध से ज्यादा भयंकर है। यरुशलम में धार्मिक तनाव से पैदा हुई यह हिंसा विध्वंसक युद्ध की याद दिलाती है। गाजा में दिन भर इजराइली हवाई हमलों की आवाज सुनी गई और जिन

इमारतों को निशाना बनाया गया, वहां से धुएं का गुबार उठता देखा गया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में नेतन्याहू ने कहा कि हमास और छोटे इस्लामिक जिहादी चरमपंथी समूहों ने ''कीमत चुकायी है और मैं आपको यहां बता दूं कि वे अपनी आक्रामकता के लिए भारी कीमत चुकाएंगे।''

उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने दर्जनों चरमपंथियों को मार गिराया और उनके सैकड़ों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, ''इस अभियान में वक्त लगेगा। दृढ़ संकल्प, एकता और ताकत से हम इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करेंगे।'' वह एकता के प्रदर्शन के तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एवं रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज के साथ खड़े दिखाई दिए। गैंट्ज ने कहा, ''कई ठिकानों को निशाना बनाया जाना है। यह तो बस शुरुआत है।'' वहीं तनाव के और बढ़ने का संकेत देते हुए इजराइल ने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की बात कही है। सेना ने कहा कि वह गाजा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और रक्षा मंत्री ने 5000 आरक्षित सैनिकों को वहां भेजने का आदेश दिया है। यह हिंसा ऐसे समय पर हो रही है जब रमजान चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि यरुशलम में और उसके आसपास इजराइली पुलिस की असंवेदनशीलता के कारण अशांति फैली। वहीं पूर्वी यरुशलम के पास शेख जर्रा में भी हिंसा के हालात बने जहां बड़ी संख्या में फलस्तीनियों को यहूदी निवासियों द्वारा निकाले जाने का खतरा है। गत सप्ताहांत अल अक्सा मस्जिद में झड़प हुई थी। चार दिनों तक इजराइली पुलिस ने फलस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले और हथगोले दागे। सोमवार शाम से हमास ने गाजा से रॉकेट दागने शुरू कर दिए और यहां से तनाव बढ़ता चला गया। हमास के निर्वासित नेता इस्माइल हानियेह ने टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा कि इजराइल पर इस हिंसा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ''इजराइली अतिक्रमण के कारण यरुशलम में हिंसा हुई और इसकी लपटें गाजा तक पहुंच गई।'' फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गाजा में मृतकों की संख्या के बारे में नहीं बताया है लेकिन इस्लामिक जिहाद ने गाजा सिटी में एक अपार्टमेंट पर हुए हवाई हमले में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है जो उसकी सशस्त्र शाखा के वरिष्ठ सदस्य थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 बच्चे और एक महिला भी मारी गई है।

काबुल के नजदीक एक शहर पर तालिबान ने जमाया कब्जा, रमजान में मारे 255 नागरिक

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में हिंसा के बीच तालिबान राजधानी काबुल के निकट वारदाक प्रांत में नेरख जिले पर कब्जा जमा लिया है। रमजान में ईद से पहले तीन दिन के संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद भी तालिबान ने यह हमला किया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एफडीडी के लॉन्ग वॉर जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। खामा प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान को करारा जवाब दिया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी ढेर हुए हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा, 'नेरख जिले के पुलिस मुख्यालय, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और बड़ी संख्या में आर्मी बेस पर कब्जा जमा लिया गया है।' तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हमने दुश्मनों के कई सैनिकों को मार दिया है। इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों को हमने जिंदा अगवा कर लिया है। सैनिकों के तमाम हथियारों, गोला बारुदों और सैन्य वाहनों को भी कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान में रमजान महीने के दौरान ही तालिबान की ओर से की गई हिंसा में 255 नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा 500 लोग जख्मी हुए हैं। तालिबना ने रमजान महीने के दौरान ही 200 बम धमाके किए हैं और 15 आत्मघाती हमले किए हैं। टोलो न्यूज ने गृह मंत्रालय के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। यही नहीं रविवार को

तालिबान ने ईद से पहले तीन दिन के संघर्ष विराम का भी ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद भी उसने एक बार फिर से हिंसा शुरू कर दी है। ईद से पहले तालिबान के शर्मनाक हमलों की जमकर निंदा की जा रही है। बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया है। अमेरिका की ओर से 11 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को स्वदेश बुलाने की बात कही गई है। इस ऐलान के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से हिंसा जारी है।

अफगानिस्तान में हो रहे हमलों के लिए चीन ने अमेरिका को ठहराया दोषी, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

चीन ने अफगानिस्तान में हो रहे हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिकी सेना की अचानक वापसी से काबुल में विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद 60 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर छात्राएं थीं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के अनुसार, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि चीन हमलों से स्तब्ध है और मौत के लिए गहरा दुख प्रकट करता है।

उन्होंने कहा, 'यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में अफगानिस्तान से सेना को पूरी तरह से वापस लेने की अमेरिका की घोषणा के बाद पूरे देश में सिलसिलेवार तरीके से विस्फोट हो रहे हैं। वहां की सुरक्षा स्थिति बिगड़ती जा रही है। शांति और स्थिरता के साथ-साथ लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी खतरा है।' चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, 'चीन अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों को बुलाकर देश और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। एक जिम्मेदार तरीके से बाहर निकलता है और अफगान लोगों पर अधिक उथल-पुथल मचाने से बचता है।' अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस महीने की शुरुआत में 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से हटने के उद्देश्य से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस साल उसकी 20वीं बरसी होगी। इस हमले के बाद से लगातार अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा संघर्ष है।

एससीएमपी ने बताया कि बीजिंग ने लंबे समय से आशंका जताई है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता इस्लामिक कट्टरवाद को जन्म देगी और चीन के मुस्लिम शिनजियांग क्षेत्र में फैल जाएगी। अमेरिका द्वारा सैनिकों की वापसी से तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि बीजिंग अफगानिस्तान में सैनिकों को तैनात करने की संभावना नहीं है, लेकिन चीन सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ काम कर सकता है। शनिवार दोपहर को काबुल के पश्चिम में सईद-उल-शुहादा हाई स्कूल के पास कम से कम तीन विस्फोट हुए। टोबो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काबुल स्कूल में बम विस्फोट में 63 लोग मारे गए और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी निंदा की थी। हालांकि, तालिबान ने हमले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने एक ट्वीट में कहा था, ÷हम काबुल के दशती बारची में नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं।'

पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का कश्मीर राग बरकरार, भारत से इस शर्त पर वार्ता को तैयार

इस्लामाबाद । अपने प्रिय कश्मीर राग अलापने का एक भी मौका न छोड़ने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से यह राग छेड़ा है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता है तब तक उनका देश भारत से वार्ता नहीं करेगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े हुए थे। इमरान खान ने कहा, 'जब तक भारत पांच अगस्त के फैसले वापस नहीं लेता है... पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर भारत से वार्ता नहीं करेगी।' इमरान खान एक लाइव प्रसारण सत्र के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के साथ वर्तमान में कोई वार्ता नहीं हो रही है, लेकिन अगर नई दिल्ली कश्मीर पर अपनी नीतियों में बदलाव करता है और कश्मीर के लोगों को राहत देता है तो वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मुद्दा नहीं हो सकता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा पर है और इस पर सुरक्षा परिषद् के कई प्रस्ताव हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश अपनी समस्याओं का हल करने में सक्षम है।

चीन के मुस्लिम बहुल इलाकों में आधी हुई जन्म दर, दुनिया में सबसे बड़ी गिरावट

बीजिंग। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार किए जाने की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में 2017 और 2019 के बीच जन्म दर में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। यह गिरावट इसलिए ध्यान खींचती है क्योंकि हाल के इतिहास में किसी भी क्षेत्र में जन्म दर में आई यह सबसे अधिक गिरावट है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्मदर 48.74 फीसदी तक कम हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक 'ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, उन इलाकों में 48.74 प्रतिशत की गिरावट आई है जहां उइगर, कजाख और अन्य बड़े मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक रहते हैं। यह रिपोर्ट चीनी सरकार के करीब एक दशक के आंकड़ों पर आधारित है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक क्षेत्र में 2017 और 2018 के बीच भी जन्म दर 43.7 प्रतिशत गिरी और 1 लाख 60 हजार बच्चों का ही जन्म हुआ। एसपीआई के शोधकर्ता और रिपोर्ट के सह-लेखक नाथन रसर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने जब से वैश्विक जन्म आंकड़ों का संग्रह शुरू किया है जब से 71 वर्षों में जन्म दर में यह गिरावट अभूतपूर्व है। इसने सीरियाई गृह युद्ध और रवांडा तथा कोलंबिया में नरसंहार के दौरान जन्म दर में आई गिरावट को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय और शिनजियांग सरकार ने अभी इस पर टिप्पणी नहीं की है।

फलस्तीनी चरमपंथियों के रॉकेट हमले में इजराइल में भारतीय महिला की मौत

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

यरूशलम। गाजा से फलस्तीनी चरमपंथियों के रॉकेट हमले में इजराइल में 30 वर्षीय भारतीय महिला की मौत हो गई। केरल के इडुक्की जिले की रहने वाली सौम्या संतोष इजराइल के अशकेलॉन तटीय शहर के एक घर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। गाजा पट्टी की सीमा से लगे अशकेलॉन में फलस्तीनी चरमपंथियों ने हमला किया। गाजा के चरमपंथियों ने सोमवार शाम से इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे और मंगलवार रात नौ बजे तक (स्थानीय समयानुसार) हिंसा में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाकर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि फलस्तीनी चरमपंथियों के हमले में मारी गई भारतीय महिला पिछले सात साल से इजराइल में रह रही थी और उसका नौ साल का बेटा है, जो उसके पति के पास केरल में रहता है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि भारतीय महिला जिस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की देखभाल करती थी, वह घर पर सीधे गिरे रॉकेट के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चैनल 12 ने बताया कि रॉकेट हमले की स्थिति में रक्षा के लिए आश्रय स्थल महिला के घर से एक मिनट की दूरी पर है, लेकिन वे समय पर वहां नहीं पहुंच सकीं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के दौरान 'आयरन डोम' बैटरी (सभी मौसम में कारगर वायु रक्षा प्रणाली, जो कम दूरी के रॉकेट बीच में रोककर नष्ट कर देती है) में तकनीकी खामी आ जाने से वह कुछ रॉकेटों को बीच में नहीं रोक पाई और इसी कारण लोग हताहत हुए। अशकेलॉन के मेयर टोमर ग्लैम ने बताया कि इलाके के करीब 25 प्रतिशत निवासियों के पास रॉकेट हमले की स्थिति में किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा, ''जब सामान्य जीवन मिनटों में आपात स्थिति बन जाए, तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना असंभव हो जाता है।'' भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''मैं इजराइल की ओर से सौम्या संतोष के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, जिनकी निर्दोष लोगों पर किए गए हमास के आतंकवादी हमले में मौत हो गई।'' केरल में सौम्या के परिवार ने बताया, जब हमला हुआ उस समय वह अपने पति संतोष से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी। संतोष के भाई साजी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''मेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान एक जोरदार आवाज सुनी और अचानक फोन कट गया। इसके बाद हमने वहां पर मलयाली मित्रों को फोन किया। तभी हमें हमले के बारे में पता चला।'' केरल के नवनिर्वाचित विधायक मणि सी कप्पन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हजारों केरलवासी इजराइल में डर के माहौल में रह रहे हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील की।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

कोरोना के बीच दक्षिण भारत में भयानक चक्रवाती तूफान की चेतावनी, 16 मई को अलर्ट

नई दिल्ली। पूर्व-मध्य अरब सागर में आने वाले दिनों में एक चक्रवाती तूफान के आने की संभावना है। यदि इस तरह का चक्रवाती तूफान वास्तव में आकार लेता है, तो यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा और इसका नाम म्यांमार द्वारा टुकटै दिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग (ढ्ढरूष्ठ) ने भविष्यवाणी की है कि भारत के पश्चिमी तट पर 16 मई तक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। वास्तव में लक्षद्वीप के निचले इलाकों में 15-16 मई तक बाढ़ आ सकती है। आईएमडी के अनुसार, 14 मई के आसपास दक्षिण-पूर्व अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 14 मई तक लक्षद्वीप क्षेत्र से सटे दक्षिण-पूर्व अरब सागर में उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है साथ ही यह और तेज होने की संभावना है। 16 मई के आसपास पूर्वी-मध्य अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान में टकरा सकता है। यह तूफान उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ने बढ़ रहा है। इस तुफान से लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तट प्रभावित होने की संभावना है।

ओडिशा में जिन लोगों के पास पहचापत्र नहीं होगा उन्हें भी लगाया जाएगा कोविड-19 रोधी टीका

भुवनेश्वर। ओडिशा में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10,982 नए मामले सामने आए तथा 17 संक्रमितों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बीच राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाने का फैसला किया है जिन्हें संक्रमण का जोखिम अधिक है लेकिन जिनके पास कोई पहचापत्र नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य पीके महापात्र ने कहा कि पहचापत्र के अभाव में ऐसे लोगों को टीके से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ''ऐसे संवेदनशील लोगों को पहचापत्र नहीं होने की स्थिति में टीका लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें खानाबदोश लोग, कैदी, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रहने वाले लोग, वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग, भिखारी आदि शामिल हैं।'' मंगलवार को 49,191 नमूनों की जांच के बाद ये नए मामले सामने आए। यहां जांच के बाद संक्रमण की दर (टेस्ट पॉजिटिविटी रेट या टीपीआर) 22.32 फीसदी है। राज्य में टीपीआर शुक्रवार से 20 फीसदी से अधिक बनी हुई है। राज्य में फिलहाल 98,230 संक्रमितों का उपचार चल रहा है।

राहुल और प्रियंका ने कोविड एवं टीकाकरण की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण एवं टीकाकरण की स्थिति को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घर-घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली देना देशवासियों के साथ धोखा है। उन्होंने ट्वीट किया, ''सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मज़ाक़ है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन-अस्पताल-दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है।'' प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन टीके की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82 फीसदी की गिरावट आई।''

ठाणे के 94 प्रतिशत से अधिक पुलिसकर्मियों ने ली टीके की पहली खुराक

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 94 प्रतिशत से अधिक पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ले ली है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस संक्रामक रोग की शुरुआत से अब तक महाराष्ट्र में यहां कुल 2,147 पुलिसकर्मी कोविड-19 से पीड़ित पाए जा चुके हैं और उनमें से 35 की इस महामारी के कारण मौत हो गई। इसमें बताया गया कि अभी तक ठाणे में 94.76 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को पहला टीका लग गया है जबकि 78.72 प्रतिशत को दूसरा टीका भी लग गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अभी यहां कोरोना वायरस से पीड़ित 34 पुलिसकर्मी इलाज करा रहे हैं। इस बीच, ठाणे के महापौर नरेश म्हास्के ने बताया कि बुधवार से यहां विवियाना मॉल की पार्किंग में 60 साल से अधिक की आयु वाले लोगों के लिए ड्राइव-इन टीकाकरण केंद्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में एक दिन में 100 वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए जाएंगे।

केंद्र ने उत्तराखंड को भेजी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, कोरोना संकट से जूझ रहा है राज्य

देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बुधवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए भेजा गया। यहां हर्रावाला रेलवे स्टेशन से प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न स्थानों के लिए ऑक्सीजन वाहनों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट किया तथा कहा कि विषम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की तरफ से राज्य को भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी लेकिन जैसे-जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तर बढ़ रहे हैं वैसे ही खपत भी बढ़ती जा रही है।

देश में वैक्सीन की किल्लत क्यों? वैक्सीन विदेश भेजे जाने पर भाजपा ने दी यह सफाई

लखनऊ। (एजेंसी)।

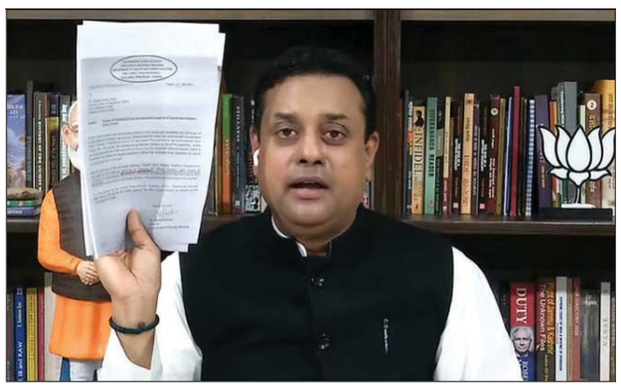

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी मारामारी जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर वैक्सीन सप्लाई को रोकने का आरोप लगा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के कारण भारत बायोटेक ने दिल्ली को 67 लाख कोवैक्सीन देने से मना कर दिया। इसके अलावा विपक्ष के शासन वाले राज्य लगातार केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। देश में भले ही यह दावा किया जा रहा है कि टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है लेकिन सच यही है कि कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से कई टीका केंद्र बंद हो पड़े हैं।

विपक्ष के इन आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया है। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी वैक्सीनेशन के मसले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वैक्सीन को विदेश भेजे जाने पर संबित पात्रा ने कहा कि 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोज हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसमें मात्र 1 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मदद के रूप में भेजा गया है। बाकी 84त्न वैक्सीन लायबेलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था चाहे किसी कि भी सरकार होती। उन्होंने कहा कि अपने देश के पड़ोसी 7 राष्ट्रों को हमने 78.5 लाख वैक्सीन की डोज मदद के रूप में दी है। बाकी 2 लाख डोज यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को दिए हैं। क्योंकि 6,000 से ज्यादा हमारे देश के जवान अलग-अलग देशों में पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं।

पात्रा ने आगे कहा कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों ने पहले से ही देश के बाहर से रॉ-मैटेरियल लिया था। इस वक्त करार हुआ था कि इससे जब वैक्सीन तैयार होगी तो उसमें से कुछ वैक्सीन उन देशों को भी दिया जाएगा। ये commercial liability है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई, जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सुबह आठ बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, उपचाराधीन मामले कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87 प्रतिशत है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.04 प्रतिशत हो गई है।

कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिये पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कर्मी माना जाए: फडणवीस

मुंबई। (एजेंसी)।

महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मांग की कि पत्रकारों, और छायाकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण में अग्रिम पंक्ति का कर्मचारी माना जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि देश के कम से कम 12 राज्यों ने पत्रकारों और छायाकारों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के तौर पर मान्यता दे कर उनका टीकाकरण कराया है। फडणवीस ने कहा, 'देश में करीब 12 राज्यों ने पत्रकारों और छायाकारों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी के तौर पर मान्यता दी है और उन्हें टीका लगवाया है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में इस बारे में फैसला अब तक लंबित है।'

उन्होंने कहा कि इस महामारी की पहली और दूसरी लहर की चपेट में आकर कई मीडियाकर्मियों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा, 'पत्रकारों का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। एक बार अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी के तौर पर मान्यता मिलने के बाद उन्हें टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता मिलेगी।' ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल उन प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी के तौर पर मान्यता दी है।

चुनाव के दौरान कर्मचारियों की मौत मामले में हाई कोर्ट ने लगायी सरकार को फटकार, मुआवजे का रकम पर उठाया सवाल

लखनऊ। (एजेंसी)।

प्रयागराज (उप्र)। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारियों की मृत्यु के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुआवजे का रकम बहुत कम है और मुआवजा कम से कम एक करोड़ रुपये के करीब होना चाहिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

अदालत ने कहा, ''परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा और वह भी राज्य और निर्वाचन आयोग की ओर से जानबूझकर उस व्यक्ति को आरटीपीसीआर सहायता के बगैर ड्यूटी करने के लिए बाध्य करने के चलते कम से कम एक करोड़ रुपये होना चाहिए। हमें आशा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार मुआवजे का राशि पर पुनर्विचार करेगी।'' मेरठ में एक अस्पताल में 20 मरीजों की मृत्यु पर अदालत ने कहा, ''भले ही यह एंटिजेन टेस्टिंग के लिए संदिग्ध रूप से कोरोना से मृत्यु हो, हमारा विचार है कि मृत्यु के इस तरह के सभी मामलों को कोरोना से मृत्यु के मामले के तौर पर लिया जाना चाहिए।'' अदालत ने मेरठ के मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को उन 20 मृत्यु की सटीक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। प्रधानाचार्य ने अदालत को बताया कि मृत्यु की तिथि से पूर्व, 20 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसमें से तीन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जबकि अन्य का एंटिजेन टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मचारियों एवं जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा असहयोग के मामले में अदालत ने निर्देश दिया कि हर जिले में तीन सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति इस आदेश के 48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव (गृह) सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। लेवेल 1, 2 और लेवल 3 अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने और लेवल 1 वर्ग के अस्पताल में प्रति मरीज 100 रुपये आबंटित किए जाने की जानकारी दिए जाने पर अदालत ने कहा, ''यह सभी जानते हैं कि कोविड-19 मरीजों को अत्यधिक पोषक भोजन की जरूरत होती है जिसमें फल और दूध शामिल हैं। यह समझ से परे है कि सरकार कैसे प्रति व्यक्ति 100रुपये से तीन समय के भोजन का प्रबंधन कर रही है।''

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव के इलाज के मुद्दे पर अदालत ने कहा, ''दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्हें जीवन रक्षक दवा रेमडेसिवर लेने की सलाह दी गई थी। हालांकि कागजों से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में उन्हें पहले दिन या बाद के दो दिनों में यह दवा दी गई कि नहीं।'' अदालत ने कहा, ''दस्तावेजों से पता चलता है कि 24 अप्रैल को शाम 7 बजकी 20 मिनट तक उनके शरीर में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई थी और इसके बाद स्थिति खराब होनी शुरू हुई। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि इस मामले में चूंकि रिकार्ड पूर्ण नहीं हैं, इस मामले की जांच के लिए सरकार एक समिति का गठन करे।'' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मई निर्धारित की।

महामारी से लड़ना नयी बंगाल सरकार की प्राथमिकता, रोजगार सृजन पर भी ध्यान: फिरहाद हाकिम

कोलकाता (एपी)। (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल के परिवहन एवं आवास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटना नयी सरकार की प्राथमिकता है तथा साथ ही रोजगार सृजन, अवसंरचना और कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हाकिम ने कहा कि नयी सरकार चुनाव से पहले पेश किए गए राज्य के अंतरिम बजट संबंधी वादों को पूरा करने के लिए भी काम करेगी। उन्होंने पीटीआई-के साथ साक्षत्कार में कहा, ''कोविड से निपटना प्राथमिकता है। इसके बाद, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने और नयी अवसरंचना के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनकी दीदी (ममता बनर्जी) ने पिछले बजट में घोषणा की थी।''

हाकिम ने कहा, ''कृषि क्षेत्र में राज्य की शीर्ष स्थिति को बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक होगा। मेरा मानना है कि ये मुख्य चुनौतियां हैं।'' उन्होंने कहा, ''अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें राज्य की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को पटरी पर वापस लाना है। चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों और बाहरी लोगों के बार-बार हुए दौरों की वजह से यह पटरी से उतर गई थी।''

हाकिम कोलकाता नगर निगम के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा, ''हम लगातार काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार आसानी से सभी मुद्दों से निपट सकेगी।'' हाकिम ने कोलकाता की पोर्ट विधानसभा सीट से 68,302 मतों के अंतर से चुनाव जीता था।

उन्होंने कहा, ''सच कहूं तो मुझे इतने बड़े अंतर से जीत की उम्मीद नहीं थी। मुझे यकीन था कि दीदी दो तिहाई बहुमत से सत्ता में आ रही हैं, लेकिन यह मेरी कल्पना से परे था।'' हाकिम ने कहा कि वह परिवहन और आवास विभागों की नयी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और वह मेरे जीवन का गौरव हैं। मैं दीदी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसे निभाने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा।

दिल्ली में 150 बिस्तर वाले अस्पताल को शुरू करने लिए लाइसेंस दिया जा सकता है: आप सरकार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उस 150 बेड (बिस्तर) वाले 'मल्टी-स्पैशिएलिटी' (बहु-विशेषज्ञ) अस्पताल को शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, जिसे उसकी मूल कम्पनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के कारण बंद कर दिया गया था बशर्ते उसका अपेक्षित बुनियादी ढांचा ठीक हो। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस पर आने वाले खर्च और कोविड-19 केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक चीजों का भार नहीं उठा सकती, क्योंकि उसके खुद के अस्पतालों में कर्मचारियों, दवाइयों और उपकरणों की कम है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि अगर अदालत निर्देश देती है और 'फेब्रिस मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल' दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम में दिए गए मापदंडों को पूरा करता है तो उसे शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। अदालत के दिल्ली सरकार के 'मल्टी-स्पेशलिटी' अस्पताल को शुरू नहीं करने के तर्क पर सवाल उठाने के बाद यह हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर छह मई को दिल्ली सरकार से ''लीक से हटकर सोचने'' के लिए कहा था।अदालत ने कहा था कि ''हम सामान्य परिस्थिति में नहीं है'' और राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एक पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा था, ''150 बिस्तर उपलब्ध हैं। हम हर जगह बिस्तर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम हर दिन इसके लिए लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें यह तर्क समझ नहीं आ रहा है।'' अदालत ने कहा था, ''पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वह (याचिकाकर्ता डॉक्टर) अपना अस्पताल खोलने की पेशकश दे रहे हैं, वह अपनी मेडिकल टीम लाने के लिए तैयार हैं, आपको और क्या चाहिए?'' दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अस्पताल ने 2018 और 2019 में कई बार कहे जाने के बाद भी अपनी मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट देनी बंद कर दी है। उसने कहा, 'अस्पताल में तैनात सरकारी सम्पर्क अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक को सूचित किया था कि उक्त परिसर में कोई नर्सिंग होम गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। इसके बाद, निदेशालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसे पूर्ववत् लौटा दिया गया था। कारण बताने के लिए उक्त नोटिस 14 अगस्त, 2020 को ई-मेल के जरिए भी भेजा गया था।'' सरकार ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं देने के कारण पिछले साल सितम्बर में 'फेब्रिस हॉस्पिटल' का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय डॉ. राकेश सक्सेना की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महामारी के दौर में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 'फेब्रिस मल्टी स्पैशिएलिटी हॉस्पिटल' शुरू करने की अनुमति मांगी गई है।

केंद्र सरकार आपदा में अवसर वाली सरकार, जरूरी चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी हटाई जाए: कांग्रेस

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर 'आपदा में अवसर वाली सरकार' होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे अपना राजधर्म निभाते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से मुक्त करना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह दावा भी किया कि अगर टीकों, ऑक्सीजन सांद्रक और रेमडेसिविर इंजेक्शन से जीएसटी हटा ली जाए तो जनता एवं राज्य सरकारों को 6000 करोड़ रुपये का वार्षिक फायदा होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''टीके पर पांच फीसदी पर जीएसटी ली जा रही है। यह सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन पर 12 फीसदी और ऑक्सीजन सांद्रक पर 12 फीसदी की जीएसटी वसूल रही है। वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन पर भी 12 फीसदी तथा एंबुलेंस पर 28 फीसदी की जीएसटी ली जा रही है।'' वल्लभ ने कहा, ''यह सरकार 'आपदा में अवसर वाली सरकार' है। मेरा सरकार से कहना है कि वह इतनी बेरहम नहीं बने। वह सकारात्मकता का प्रसार करने की बात करती है,लेकिन जीएसटी वसूल रही है। क्या देश के लोगों ने आप (सरकार) पर विश्वास जताकर पाप कर दिया कि उनके साथ आप यह व्यवहार कर रहे हैं?'' उन्होंने दावा किया, ''टीके, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सांद्रक से जीएसटी हटा दी जाए तो देश के लोगों को 6000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इन 6000 करोड़ रुपये से 12 लाख ऑक्सीजन सांद्रक खरीदे जा सकते हैं। इतने पैसे में 20 करोड़ लोगों को टीके लगाये जा सकते हैं। इतने पैसे से छह नए एम्स खोले जा सकते हैं।''

कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से आग्रह किया, ''सरकार अपना राजधर्म निभाए और जरूरी चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी हटाए।'' उन्होने कहा कि सिर्फ बातें करने से सकारात्मकता नहीं आएगी, बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने के बाद ही सकारात्मकता की बात हो सकती है।

कांग्रेस की डूबती नाव को बचाने के लिए शिवसेना से ताय मशवरा ले रही हैं सोनिया गांधी?

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भले ही कहें कि वे शिवसेना का मुखपत्र 'सामना' नहीं पढ़ते लेकिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने उसके उस लेख पर ध्यान दिया था जिसमें पूछा गया था कि क्यों उनकी पार्टी असम तथा केरल में मौजूदा सरकारों को हरा नहीं सकी। मराठी समाचार पत्र में एक संपादकीय में यह भी पूछा गया कि कांग्रेस में जमीनी नेतृत्व की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस को ''भविष्य में मजबूत विपक्षी पार्टी'' के तौर पर काम करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में कहा कि उन्होंने 'सामना' पढ़ना बंद कर दिया है और शिवसेना को उनकी पार्टी तथा उसके नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सामना में बुधवार को कहा गया, ''सोनिया गांधी ने पूछा कि असम और केरल में अच्छा मुकाबला करने के बावजूद कांग्रेस मौजूदा सरकारों को क्यों नहीं हरा पायी। यही सवाल सामना में इस स्तंभ के जरिए पूछा गया था।'' शिवसेना ने कहा कि अगर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संपादकीय पढ़ा होता और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को सोनिया गांधी के सामने रखा होता तो यह अच्छा होता। शिवसेना महाराष्ट्र में राकांपा और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। उसने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा तथा पुडुचेरी के एन रंगासामी सभी पूर्व कांग्रेस नेता हैं।

संपादकीय में कहा गया, ''इन तीनों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और फिर ये मजबूत नेता बनकर उभरे।'' शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और कड़ी आलोचना के बावजूद वह हमेशा अपनी बात रखते हैं। संपादकीय में दावा किया गया है, ''कोविड-19 महामारी के बीच राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर केंद्र की आलोचना की और सुझाव भी दिए। उनकी बुरी तरह आलोचना करने के बाद सरकार को उनके द्वारा दिए सुझावों पर फैसला लेना पड़ा।''

शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के ''सेनापति'' हैं और सरकार पर उनके हमले सटीक और मुद्दों पर आधारित होते हैं। संपादकीय में दावा किया गया कि लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई और कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ''आक्रोश'' है। शिवसेना ने कहा, ''इस वक्त सभी मुख्य विपक्षी दलों को 'ट्विटर' शाखाओं से राजनीतिक जमीन पर आना होगा..जमीन पर आने का मतलब महामारी के वक्त में भीड़ इकट्ठा करना नहीं है बल्कि हर दिन सरकार से सवाल करना और उसे जिम्मेदार ठहराना है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौयो द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)